

उपाध्यक्ष महोदय : मुझ को आपका पत्र मिला था । मगर उसमें यही था कि आप चाहते हैं कि आप कोई मोशन करें । जब मोशन के सामने होगी तभी मैं कंसिडर कर सकता हूँ ।

श्री सुभाषचन्द्र राव : प्रत्युक्ति चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब नोटिस देंगे तब होगा । जब आपने नोटिस नहीं दिया तो मैं किस को कंसिडर करूँ । जब आप नोटिस देंगे, तो उस पर बिचार करके मैं उस चीज को आपके सामने लाऊंगा ।

12.10 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, a copy of Notification No. G.S.R. 349 dated the 28th March, 1959. [Placed in Library See No. LT-1349|59.]

BUSINESS OF THE HOUSE

The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): With your permission, and on behalf of Shri Satya Narayan Sinha, I rise to announce that Government business in this House for the week commencing 14th April, 1959, will consist of:—

- (i) Further discussion and voting on the Demands for Grants of the Ministry of Community Development and Co-operation;
- (ii) Discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Ministries of Commerce and Industry, and Finance;
- (iii) Submission to the vote of the House of the outstanding Demands for Grants; and
- (iv) Consideration and passing of the Finance Bill, 1959.

RE: DISCUSSION OF REPORT OF COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians): May I know from the Home Minister whether he is going to lay on the Table of the House the report of the Committee of Parliament on the Official Language, and if so, when, and what time will be given to the Members of this House to study it, and above all, what time will be allotted for the discussion of this rather controversial report?

The Minister of Home Affairs (Shri G. B. Pant): I propose to lay the report on the Tables of both Houses, after the Rajya Sabha has started its session, on the 20th or 21st or 22nd instant or about that time.

As to whether it will be taken up for discussion, and when, it is for the House to decide and for the Business Advisory Committee That does not rest with me.

12.12 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS—contd.

Ministry of Rehabilitation—contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Rehabilitation. Out of 4 hours allotted for these Demands, 1 hour and 56 minutes now remain.

What time does the hon. Minister propose to take?

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna): About 45 minutes or up to 1 hour I shall start at quarter past one of the clock.

Mr. Deputy-Speaker: Yes, I shall call him at 1.15 p.m. Now, Shri Prakash Vir Shastri may continue his speech.

*Moved with the recommendation of the President.

श्री प्रकाश और शास्त्री (इयाँ) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहली बात में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अब तक जिस प्रकार की परम्परा रही है कि किसी भी मंत्रालय के अनुदानों पर जब चर्चा प्रारम्भ होती है तो उस में जहाँ बहुत से माननीय उपाध्यक्ष मंत्री में अपने भाषण देते हैं वहाँ हिन्दी में बोलने वालों का अनुपात भी पर्याप्त रहता है। परन्तु माननीय मंत्री महोदय की ओर से उत्तर दिया जाता है तो वह प्रायः अंग्रेजी में ही होता है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले अधिवेशन में एक बार हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने विदेश मंत्रालय पर हुई बहस का उत्तर अंग्रेजी में ही दिया था लेकिन जिन सदस्यों ने हिन्दी में चर्चा की थी, उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया था, उसी तरह से

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन की डिमांड्स पर भी ऐसा ही ?

श्री प्रकाश और शास्त्री : इतना कह कर के अब मैं रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की जो डिमांड्स हैं, उन पर चर्चा प्रारम्भ करता हूँ।

मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब पुनर्वास विभाग की ओर से यह सूचना इस सदन को और बाहर भी दी गई कि अवगत एक वर्ष के पश्चात् इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन प्राश्चर्य इस बात का है कि जो दायित्व इस मंत्रालय को सौंपे गये थे उन दायित्वों को वह अभी तक पूरी तरह से निभा नहीं पाया है और जो विस्थापित भाई उधर से उधर भाये हैं उनकी समस्यायें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ वहाँ पर कुछ स्थान इस प्रकार के हैं जहाँ पाकिस्तान से भाये हुए विस्थापित भाई रहते हैं। पुनर्वास मंत्रालय की ओर से जो तीन बार

टाउनशिप बसावे मये हैं जैसे राजपुरा है, हस्तिनापुर है, फरीदाबाद है और कुछ दूसरे इस प्रकार के टाउनशिप हैं, वहाँ पर बसे हुए विस्थापितों के बारे में शासन की नीति यह है कि वहाँ पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र बनाये जायें, जिससे कि उन लोगों को रोजी देने का प्रबन्ध हो सके और उनके परिवारों के भरणपोषण की व्यवस्था सुगमता के साथ हो सके।

जहाँ तक राजपुरा टाउनशिप का सम्बन्ध है, उसके बारे में मुझे बहुत अधिक विस्तृत जानकारी नहीं है, परन्तु इतना मैं अवश्य जानता हूँ और यह इस आधार पर कि मुझे दो तीन बार वहाँ जाने का अवसर मिला है कि वहाँ पर एक बिस्कुट का बहुत बड़ा कारखाना है जो वहाँ पर पहले से ही चला था। उसके प्रतिरिक्त अभी तक राजपुरा टाउनशिप को कोई औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई है।

जहाँ तक फरीदाबाद का सम्बन्ध है, वहाँ पर ३५,००० के लगभग विस्थापित भाई रहते हैं। हमारे पुनर्वास मंत्रालय ने फरीदाबाद को औद्योगिक क्षेत्र बनाने का पर्याप्त प्रयास किया है। लेकिन दुर्भाग्य वहाँ के निवासियों का यह है कि इन फैक्ट्रियों में या इन कारखानों में जिन लोगों को रखा गया है उसमें फरीदाबाद के लोगों का अनुपात जितना अपेक्षित था उस अनुपात से नहीं रखा गया है और सब से बड़ी कठिनाई की बात यह है कि फरीदाबाद का प्रबन्ध करने वाला जो एक डिवेलपमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति बिठाये गये हैं कि जो पैसा याफ्त लोग थे। उनको वहाँ पर नियुक्त करने की दृष्टि से अमर शासन का सीधा हस्तक्षेप वहाँ पर होता तो इस प्रकार के लोग बीच में नहीं आ सकते थे और उनके द्वारा लोगों की जो समस्यायें हैं, उनको सुलझाने में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, वे हमारे माननीय पुनर्वास मंत्री महोदय के सामने हैं।

सब से बड़ी कठिनाई इस समय वहाँ के विस्थापितों के सामने यह है कि उनको तसाने के लिए जो क्वार्टर बनाये गये हैं, जैसा कि वास्तव का कहना है कि ७० बार्ड ३० फुट का जो क्वार्टर है, उसकी लागत कीमत २६०५ रुपये तै की गई है लेकिन जो विस्थापित भाइयों से कीमत सी जायेगी तीस वर्षों में सूब-दर-सूब लगा करके वह कीमत ४२७५ के लगभग बैठती है। इस विषय में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि जो भाई बंगाल से या कंटियर से या सिध से या बंगाल से उजड़ कर भाये हैं, यदि देखा जाये तो उन्होंने यह तपस्या, उन्होंने यह बलिदान और उन्होंने यह मुसीबत देश की स्वाधीनता के लिए ही भोस ली है और हमारी नैतिकता का यह तकाबा नहीं है कि जो क्वार्टर हमको २६०० में पड़ा है, उसकी कीमत हम सूब-दर-सूब लगा करके बसूल करे। वे लोग इतनी कीमत भदा करने की स्थिति में भी नहीं है। ४२७५ रुपये उन से लिये जायें, यह स्थिति ठीक नहीं है।

दूसरी समस्या जो फरीदाबाद टाउनशिप की है वह यह है वहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिस को बादशाह खां अस्पताल कह कर पुकारा जाता है। १५० के लगभग बहा बँहस हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह धाव कर आश्चर्य होगा कि अभी तक इस इतने बड़े अस्पताल में किसी भी विषय का कोई स्पेशलिस्ट वहाँ नहीं रखा गया है। कुछ समय पहले वहाँ एक सर्जन था लेकिन अब बहुत समय से कोई सर्जन भी वहाँ नहीं है। इसका अभिप्राय यह होता है कि जहाँ सर बालीस के लगभग फीकटिया हैं, अगर उनमें से किसी फीकट्री में किसी मजदूर की हड्डी टूट जाती है या और इस प्रकार का कोई सीरियस इकिसिडेंट हो जाता है तो उसके इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए, उसको दिल्ली भागना पड़ता है। दूसरी भाषा में यह कहना होगा कि फरीदाबाद का विस्थापित अगर मरना भी चाहे तो वह दिल्ली में आकर मर सकता है, फरीदाबाद में उसके मरने की भी गुंजाइश

नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ के अस्पताल में है। हमारे पुनर्वास मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि फरीदाबाद में रहने वाले ३५,००० इन विस्थापितों में से लगभग १०,००० विस्थापित इस प्रकार के हैं कि जिन के परिवार वालों को एक समय का ही केवल भोजन मिल पाता है। जो प्राथिक दृष्टि से इतने दुर्बल है वे अपना इलाज करवाने के लिए अगर अस्पताल में जाते हैं तो परकी देकर दवाई लेने के लिए उनको बाजार में भेज दिया जाता है। इतना बड़ा अस्पताल है और इस पर सरकार लाखों रुपये व्यय करती है, फिर भी वहाँ पर से बीमार व्यक्तियों को निराश हो कर लौटना पड़े, यह हमारे शासन के लिए कोई श्रेयस्कर स्थिति नहीं है।

फरीदाबाद में फीकटियों पर गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया है। १८-२० लाख रुपये के करीब बकिंग कैपिटल के रूप में दिया है और बिल्डिंग कैपिटल के रूप में लगभग २६ लाख रुपया फरीदाबाद को दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, धीरोगिक क्षेत्र बनाने के पीछे शासन की नीति यह है कि जो लोग डेहरा इस्माईल खां और कंटियर से भाये हैं, उनको उन फीकटियों के अन्दर रूपाया जा सके। लेकिन अभी तक फरीदाबाद के अन्दर इस प्रकार की जो फीकटियाँ हैं उनको अधिक से अधिक रुपया दिये जाने के पश्चात् भी एक भी मजदूर उनमें ऐसा नहीं है, जोकि फरीदाबाद का रहने वाला हो। उदाहरण के लिए मैं डोगरा स्टील वर्क्स का नाम लेता हूँ। इस फीकट्री को ८६,००० रुपया बकिंग कैपिटल के रूप में दिया गया है लेकिन इतना रुपया देने के बावजूद भी अभी तक डोगरा स्टील वर्क्स के अन्दर एक मजदूर भी फरीदाबाद का रहने वाला नहीं लगाया जा सका है। इसी तरह से फरीदाबाद क्वेरी वर्क्स को जिसे ३०,००० रुपया दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, उसमें एक भी मजदूर इस प्रकार का नहीं है जो फरीदाबाद का रहने वाला हो। अब आप धीरोगिक क्षेत्र बनाते हैं और

[श्री प्रकाश शीर साल्मी]

शासन की ओर से जन्मो पैसा दिया जाता है जो वह कहां तक उचित है कि कहां के रखने वालों में से एक को भी मजदूर की नौकरी पर न खयाया जाये और माहुर के लोगों को वहां खपाया जाये ।

वहां पर फेड्टीज में जो नियुक्तिया की नी जाती हैं, उनका तरीका यह है कि प्राय उनको अस्थायी रूप से, टैम्पोरेरी रूप से रखा जाता है और तीन महीने के पश्चात् उनको दुबारा नौकरी के लिए, सर्विस के लिए प्रार्थनापत्र देने पड़ते हैं। फेड्टी के मालिक नौकरों के साथ यह इसलिए करते हैं कि जो लेबर के लिए आपने कानून बनाया हुआ है, उन पर वह लागू न हो सके और उस कानून के अन्तर्गत जो सुविधायें लेबर को उन्हें देनी पड़ती हैं, जो सरक्षण देने पड़ते हैं, वे लेबर को न मिले। इसलिए हर तीन महीने के बाद उन को फेड्टी मालिक के दरवाजे पर जा करके उसी प्रकार मे प्रणाम करना पड़ता है, उसी प्रकार एक दयनीय स्थिति में जा करके खड़ा होना पड़ता है और यह उन की कृपा पर निर्भर करता है कि उन को रखे या न रखे। वह रख लेते हैं लेकिन रखने के पश्चात् लेबर कानून के अनुसार उन को जो सुविधायें प्राप्त हानी चाहिये वह नहीं प्राप्त होती। हर तीसरे मास में उन की टैम्पोरेरी सर्विस दुबारा प्रारम्भ कर दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि उन की नौकरियों के सम्बन्ध में कुछ स्थायित्व प्राना चाहिये और उन को थोड़ी मजबूती मिलनी चाहिये जिस से उन की जीवन के सम्बन्ध में और भी कुछ आवश्यक सुविधायें प्राप्त हो सकें।

फरीदाबाद के अन्दर एक फेड्टी है ईस्ट इंडिया काटन मैनुफैक्चरिंग क० (प्राइवेट) लिमिटेड। उस फेड्टी के अन्दर जो कार्य होता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। पहले यह फेड्टी एक फेड्टी के रूप में सगठित हुई और अन्तर वह एक फेड्टी के रूप में काम

करती रहती तो हमारी गवर्नमेंट को ८ लाख, ३ हजार, ८८० ४० एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलते। लेकिन उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बचाने के लिये धागे बल कर इस फेड्टी को दो हिस्सों में बाट दिया। आज उस से गवर्नमेंट को केवल ६ लाख, ६५ हजार, ८२० ४० ही मिलते हैं। इस तरीके से इस फेड्टी के मालिकों ने और प्र न्वको ने १ लाख, ३८ हजार ६० ४० एक्साइज ड्यूटी के बचये। मेरा निवेदन यह है कि जब उमे औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है तो यह धाधा की जाती है कि इस औद्योगिक क्षेत्र से अधिक से अधिक आय हो सकेगी लेकिन इस प्रकार से फेड्टी के विभक्त होने के पश्चात् धाज शासन को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी वधा में हमें बहुत सावधान हो कर कार्य करना चाहिये।

मैं जो विशेष बात कहना चाहता हू अपने पुनर्वास मंत्री से वह यह कि फरीदाबाद के लोगों की खराब स्थिति को देखते हुए वहा पर क्लेम्स सेटलमेंट दफ्तर पहले फरीदाबाद में खोला गया था फिर न जाने क्यों उस क्लेम्स सेटलमेंट आफिस को वहा बुला लिया गया। फरीदाबाद के विस्थापितों की इस प्रकार की स्थिति है कि वह बार बार दिल्ली धायें और वहा धा कर प्रतीक्षा करे, फिर अगली तारीख दे दी जाय, फिर दुबारा वहा धायें और फिर अगली तारीख दे दी जाय। इस प्रकार की दयनीय स्थिति में उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह क्लेम्स सेटलमेंट का आफिस दुबारा फरीदाबाद के अन्दर स्थापित कर दिया जाय जिस से वहा के गरीब लोगों की परेशानी दूर हो सके।

इस फरीदाबाद के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हू। फरीदाबाद के पांच बाडों में से न० ४ बाड हमारे पुनर्वास मंत्रालय ने इसलिये खाली छोड़ा था कि जो उन की

स्नातक स्तर पर इंजिनियरिंग की बीबीएन है उस के लिये छोटे छोटे उद्योग प्रारम्भ किये जायेंगे । वरीय छात्राभ्यासियों को उस के आचार पर कुछ बोझ भी राहत मिल जायेगी । लेकिन अभी तक, इतने वर्षों के बाद भी नं० ४ बार्ड खाली पड़ा हुआ है और सयु उद्योगों की स्थापना के लिये पुनर्वासि मंत्रालय के द्वारा कोई भी पग नहीं उठाया जा सका । जो प्रुस्तिका प्राप्त की और से प्रकाशित की गई है उस में आपने स्नातक स्तर पर इंजिनियरिंग के लिये कुछ राशि निर्धारित की है । इस आचार पर मेरा निवेदन है पुनर्वासि मंत्री जी से कि फरीदाबाद के लोगों को राहत देने के लिये ४ नं० के बार्ड में, जो कि अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है, छोटे छोटे उद्योग प्रारम्भ किये जायें जिस से फरीदाबाद के परिवारों की वेधियां और जो मजदूर हैं वह जा कर अपनी क्षुधापूर्ति के लिये वहां पर काम कर सकें और अपने निर्वाह में समर्थ हो सकें ।

इस के बाद मैं कुछ शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । अभी तक ३५ हजार की आबादी की उस बस्ती में केवल मैट्रिक तक शिक्षा देने का प्रबन्ध है । मैट्रिक के पश्चात् कुछ भी नहीं है । मैं पुनर्वासि मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि मैं ने एक बार उन से मिल कर निवेदन किया तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमारे सांस्कृतिक मंत्री को यह लिखा कि एक टेक्निकल स्कूल फरीदाबाद में खोल दिया जाय । हमारे सांस्कृतिक मंत्री ने इस विषय में बोझी सी सहानुभूति भी दिखाई । पंजाब के लिये जब हम ने लिखा तो गुड़गांव, स्वीडन तो हुआ, लेकिन फरीदाबाद के लोगों का दुर्भाग्य है कि वहां पर गुड़गांव के एक मिनिस्टर ने वह बजाय फरीदाबाद के उसे रिवाड़ी में खींच कर ले गये जबकि बगल में सिर्सों में लुहरा टेक्निकल स्कूल खुल रहा है । इस सम्बन्ध में लोगों को राहत देने के लिये अगर टेक्निकल स्कूल खोला जाय तो अच्छा है, नहीं तो फिर उच्च शिक्षा के नये विचार कालेज ही खोल विना जाय ।

इस के बाद मैं एक विशेष बात डेवेलपमेंट बोर्ड के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैंने अपने पुनर्वासि मंत्री महोदय को लिखा भी था कि डेवेलपमेंट बोर्ड में काम करने वाले जो लोग हैं उनको की सविस्तरों की गारंटी है । जब दस वर्ष पहले यह विभाग स्थापित हुआ था तो इस विभाग की स्थापना भी पुनर्वासि मंत्रालय की ओर से हुई थी, अब तक जो ६ करोड़ ६० इस फरीदाबाद की उन्नति पर खर्च किये गये हैं वे भी इसी विभाग की ओर से खर्च किये गये हैं । लेकिन दस वर्ष पश्चात् यहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के भ्रमसे जीवन का अब सम्बन्ध घाटा है तो न पंजाब गवर्नमेंट इस दायित्व को लेने के लिये तैयार होती है और न सेंट्रल गवर्नमेंट ही तैयार होती है । हमारे पुनर्वासि मंत्रालय का कहना है कि जब हम फरीदाबाद का पूरा चार्ज पंजाब गवर्नमेंट को सौंपें तो हम उनकी सविस्तर के सम्बन्ध में भी यह निवेदन करेंगे कि प्रायिदिः उनको दी जाय । लेकिन प्राथमिकता देने के साथ साथ दस दस वर्ष तक जो उन्होंने दयानतवारी के साथ सेवा की है उसके सम्बन्ध में आप क्या गारंटी देना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि दस वर्ष की सविस्तर के लिये उन्हें कुछ इस प्रकार की सुविधायें प्रवश्य मिलनी चाहियें जिससे प्रायें चल कर उनको विषकत न हो । अगर किसी भादमी को २५० ६० वेतन मिलता था उसको नये निरे से प्रारम्भ करके १०० ६० वेतन दिया जाय तो यदि वह २५० ६० के वेतन में अपने बच्चों को शिक्षा देने का भ्रम्यस्त है इसलिये १०० ६० में ऐडजस्ट करने में उसे कठिनाई होगी ।

अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह हम इलाके की ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब की समस्या है और वह सूरतक की तकावी के सम्बन्ध में है । जो वहाँ के विस्थापित उजड़ कर कैम्पों में आकर बसे थे, इस सम्बन्ध में उनको थोड़ा सा धाटा बरीरह दिया जाता था । बहुत से लोगों को देहातो में फैमाने के लिये पुनर्वासि मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि अगर वह वहाँ चले जायें तो वह

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

उनको थोड़ा सा लोन देना। हर धारणी को साढ़े तीन २० के हिसाब से धीरे छोटे बच्चों को पीने दो० २० के हिसाब से। उस समय यह सहयोग दिया गया था जोकि भव बापस लिया जायगा। हालांकि इस तरह की कोई लिखा पड़ी उस समय नहीं हुई थी कि यह ऋण है, लेकिन भव आज वह रुपया वसूल किया जा रहा है। भकेले गुडगांव जिले में २ लाख २० इस तरह का है जो वसूल किया जायगा। मेरा निवेदन यह है कि जब वह सहयोग के रूप में दिया गया था और दुखी स्थिति में दिया गया था तो या तो उस रुपये को छोड़ ही दिया जाय या फिर अगर लिया जाना है तो ३० बां में तकावी की शकल में लिया जाय। आज तहसीलदार और पटवारी उन के बरो पर धरना दिये बैठे हैं और उनकी कुकिया चल रही है। इस सम्बन्ध में थोड़ी सी सहूलियत उनको आज प्राप्त होनी चाहिये।

भव जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान दिला कर मैं समाप्त कर दूंगा। आपकी पुस्तिका में लिखा हुआ है कि १ अप्रैल, सन् १९५८ के बाद पूर्वी पाकिस्तान से प्रवाजन करने वालों को पुनर्वास की सुविधायें नहीं दी जायेंगी। मेरा निवेदन यह है कि दूसरे देशों के लोगों को तो हम अपने देश में सुविधा दे सकते हैं तब जो हमारे अपने हैं जो वहाँ की परेशानियों से तंग आकर यहाँ आ रहे हैं उनको यह सुविधा न दी जाय तो यह कहा तक ठीक होगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने यह कहा था कि भव जब हमारा बटवारा हो चुका है तो जो लोग यहाँ पर रह गये हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और जो उबर हैं उनकी जिम्मेदारी आप के ऊपर है। इसके बाद भी अगर वहाँ से लोग आते हैं मांग मांग कर तो उनकी बरती धाय हूँ मैं ताकि

हम आने वाले लोगों को बसा सकें। उसी तरह से मेरा निवेदन है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जीवन की समस्या से परेशान होकर आपका दरवाजा लटकटा रहे हैं उनकी धीरे धीरे बिबा जाय। हम शरणागत को शरण देने में सदा से निपुण बने आये हैं। इसलिये इस प्रकार का आदेश निकालना हमारे लिये प्रामाणिक बात होगी।

भव मैं विशय रूप से उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ जोकि पुराने किले के शरणार्थी हैं, जिनकी इतनी चर्चा हो चुकी है। अगर पुनर्वास मंत्रालय उनको वहाँ से हटा रहा है तो उनके लिये जमीन की व्यवस्था और मकान की व्यवस्था होनी चाहिये, मकान बनाने के लिये उनको थोड़ा सा ऋण दिया जाय।

भव इतना ही निवेदन करके मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भाई उषर से उजड़ कर आये हैं उनकी तरफ हमको अवश्य ध्यान देना होगा। हम भले हों इस बात को बड़ बड़ कर अपने भाषणों में कहें कि हमने इस देश की स्वाधीनता के लिये खून का एक कतरा नहीं बहाया, लेकिन वह लोग भी जो अपनी बहनो, अपनी माताओं, पुत्रों को छोड़ कर चले आये हैं, और आज भी जिनकी आँखों में आसू सूख नहीं सके हैं, उनको देख करके आज हमारी आत्मा टकरा टकरा कर कहती है कि उनका दायित्व हमारे ऊपर है और जब तक उनको हम अच्छी तरह से नहीं बसा सकेंगे तब तक पुनर्वास मंत्रालय का दायित्व नहीं समाप्त हो सकता।

श्री बहादुरिया (सवाई माधोपुर—रजित—अनुसूचित जातियाँ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में केवल दो चार बातें प्रश्न करके अपना भाषण समाप्त करूँगा। हमारे पुनर्वास मंत्री श्री को यह जवाब नाहि

मालूम है कि मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ एक तरह की शरणार्थी बसते हैं, दूसरी तरह लोकल हिन्दू हैं और तीसरी तरह उनके द्वारा बसाये लोग जोकि वहाँ के रहने वाले हमारे मेव भाई हैं, जो मुसलमान हैं। वह इलाका एक ऐसी जगह है जिसको देख कर बहुत से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। हमारे पुनर्वास मंत्री जी भी दो तीन बार वहाँ जा चुके हैं, यहाँ पर भी कई बार उसके ऊपर विचार विमर्श हो चुका है। उनकी जो भी तमाम समस्याएँ हैं उनको मैं छोड़ता हूँ केवल भूमि सम्बन्धी समस्या के बारे में कहना चाहता हूँ। वह भूमि तक सुलभ नहीं पाई है। वहाँ के शरणार्थियों को जमीनें देने का बहुत बड़ा सवाल है। जिस समय उनको वहाँ भेजा गया वहाँ पर उनको बाजिब तरीके से जमीनें दी गई या नहीं, उनको स्थायी तौर पर बसाया गया या अस्थायी तौर पर, आज मेरा यह विषय नहीं है, लेकिन मैं साफ तौर से जानना चाहता हूँ कि जब लोकल काश्तकारों को राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट के हिसाब से यह अधिकार दिया जा रहा है और जब यह मान लिया गया है कि जो जमीन जोतेगा वह जमीन उसकी होगी, उसको खातेदारी के राइट्स प्राप्त होंगे, तो इन शरणार्थियों के साथ यह भेद भाव क्यों बरता जाता है? मैं इसे धन्याय तो नहीं कहना चाहता लेकिन कम से कम इस तरह का भेद भाव उन के साथ नहीं होना चाहिये। जो अधिकार राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट के हिसाब से लोकल काश्तकारों को मिला हुआ है वही उनको भी दे दिया जाना चाहिये ताकि उनको यह सर्टेन्टी रहे कि वह जो जमीन जोतेगा वह उनकी रहेगी।

12.30 hrs.

[SRI BARMAN is the Chair]

जहाँ तक मालिकाना हक का सवाल है, मालिकाना हक के लिये आपने कहा कि जो वरें निश्चित की गई हैं उनके हिसाब के अगर वह कुछ खर्चा जमा करा दें तो उनको मालि-

काना हक प्राप्त हो जायेगा। जो लोग मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं वे उसको प्राप्त करने के लिये आपके पास कीमत जमा करायेंगे उनको तो आप मालिकाना हक दें देंगे लेकिन जो लोग काश्तकाराना हक लेना चाहते हैं, खातेदारी हक लेना चाहते हैं उनका भी जल्दी से जल्दी फैसला सुना दें ताकि उनको खातेदारी हक मिल जाय और वह उस भूमि पर डट कर दूसरे काश्तकारों की तरह से काश्त कर सकें। इसके साथ ही वहाँ पर दूसरे नाश्तकार भी हैं लोकल मेव भी हैं। सन् १९४७ के पहले जबकि वहाँ मेव बसते थे तो सारी जमीनों पर मेवों, लोकल काश्तकारों और हरिजनों का मालिकाना हक था। सन् १९४७ में मेवों के भाग जाने के बाद एक प्रजीब फिजा बनी। वहाँ पर शरणार्थी पहुँचे और वे उन जमीनों पर आबाद हुए और खेतीबाड़ी करने लगे। बाद में जब मेव वापिस धाये गये तो उन जमीनों पर खाली मालिकाना हक ही नहीं मांगा बल्कि उन जमीनों का कब्जा भी वापिस मांगा। अब लोकल काश्तकार जो कि जमीन पर काश्त करते थे उन्होंने मतलब किया कि हमारी जमीन हमको मिलनी चाहिये और मेव उबर उन पर क्राबिज होने का मतलब कर रहे हैं। अब वहा पर लोकल काश्तकार की, मेवों की और दूसरे रेप्यूजीड भाइयों की समस्याएँ हैं उनको ठीक से सुलझाने के लिये और सल्ल करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार कोई एक ऐसी कमेटी का निर्माण करे जोकि इस मामले को ठीक से सुलझाये जैसे पहले भी इस बारे में काफी विचार विमर्श हो चुका है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस समस्या को प्रन्तिय तौर पर जल्द से जल्द खत्म करना चाहिये मेरी यह मांग है कि मेवात में राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट के हिसाब से लोकल काश्तकारान को जो मालिकाना हक या खातेदारी का हक मिला हुआ है वह रेप्यूजीड को भी मिलना चाहिये।

दूसरा सवाल वहाँ के लैब और मकानों के बड़े हुए किराये का है। वहाँ पर उनसे काफी

[श्री महाश्वित्वा]

रेंट लिया जाता है लेकिन शोध समझ कर समझ कर करीब पर लिया जाना चाहिये। यहां पर सरकारीयों से दुगना किराया लिया जाता है। इस पर विचार हुआ कि दुगना नहीं लिया जाना चाहिये और बूक फल भी जराब हो गई इसलिये सबाया रेंट लेना चाहिये लेकिन इस सबाये को यह कह कर प्रमन में खाया जा रहा है कि यह एक साल समय के लिये ही है। अब मेरा कहना यह है कि सरकारीयों की स्थिति अच्छी नहीं है और वह यह बड़ी हुई दर का लगान देने की बिल्कुल हैसियत में नहीं है। एक बार यह तय भी हुआ कि वे अपना रेंट इंस्टालमेंट्स में देंगे लेकिन बाद में यह चीज भी पता नहीं क्यों डीली पठ गई और आज सरकारी भ्रष्टरान उनको लगान के और रेंट के कारण बहुत परेशान करते हैं और वे बेचारे अपने दुःखों और मुसीबतों की क्रियाद लेकर हमारे पास आते हैं। इसलिये हमें इस चीज को मान लेना चाहिये कि अगर हम रेस्यूचीज को उन पर मालिकाना हक नहीं देना चाहते तो मत दीजिये लेकिन कायतकाराना हक या आतेवारी का हक लोकल कायतकारान को दे देना चाहिये और जो लगान धारणने तय किया है उसके हिसाब से उनसे वसूल किया जाना चाहिये।

बहुत से भाइयों को जमीन के साथ में मकान भी मिले थे और मकान देते समय उनसे कहा गया था कि जिनके १०,००० से नीचे के क्लेम्स हैं वे अपने क्लेम्स दर्ज न करायें और उनको बैसे ही दूसरे रूप में मुआविजा दे दिया जायेगा। लेकिन बाद में यह मासूम हुआ कि उन भाइयों के जिनके कि क्लेम्स १०,००० से नीचे के थे और जिन्होंने कि उनको बया नहीं कराया उनको कुछ भी मुआविजा नहीं मिला और वह बड़ी मुआविजे के रह गये। अब जिनको धारणने जमीन भी दी है मकान भी दिये हैं जो मकान और जमीन उनको धारणने एलाट किये हैं उसके बावजूद

श्री उनको जमीन और मकान नहीं मिले हैं और वे दूसरों के क्लेम्स में हैं।

श्री वेदुर चन्द खन्ना : जमीनों क्या लोकस के पास है ?

श्री महाश्वित्वा : लोकस के पास है वा जेवों के पास है।

दूसरी बात में जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि एक एक मकान को धारणने दो-दो व्यक्तियों को दे रक्खा है। किसी भादमी को एक जमीन का टुकड़ा दिया और किसी भादमी को एक जमीन का टुकड़ा दिया लेकिन मकान एक ही दोनों को दिया है। अब होता यह है कि मकान में वह रह पाता है जो लटठबाज होता है और कमजोर और गरीब भादमी डर कर वहां से भाग लड़ा होता है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि मकान को दो हिस्सों में बांट दिया जाय और पक्का मकान उन को नहीं दे सकते तो कच्चा मकान उन के वास्ते बनवायें। धारण के वायदे के अनुसार कच्चे मकान का उस का हक है। इसलिये एक ही मकान को जो धारणने २ व्यक्तियों को दिया हुआ है वैसे न कर के या तो उन को प्रलग प्रलग मकान दीजिये या फिर उस मकान के कायदे और कानूनी तौर से दो हिस्से कीजिये ताकि यह रोजमर्रा के उठने वाले श्रमदे स्वतः हो जायें

डा० आ० श्री० खन्ने (नागपुर) . ऐसे कितने मकान हैं जहां कि एक एक में दो-दो भादमी बस रहे हैं ?

श्री महाश्वित्वा . उस की सख्या तो मुझे ठीक से मासूम नहीं है। इस का तो निनिस्टर महोदय को ज्ञान होगा।

राजस्थान में रिहूबिलिटेशन निनिस्ट्री की जो जमीन है उस का प्रमन बैसे तो राज-

सरकार के हाथ में रहता थाया है लेकिन हो वह रहा है कि इंतजाम तो राजस्थान गवर्नमेंट करती है लेकिन अड़गा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती रहती है और इस अड़गेबाजी के कारण वहाँ के रेवेन्यू आफिसर्स काफ़ी परेशान होते हैं और वे बेचारे इस परेशानी में रहते हैं कि किस को एलाट करें और किस को एलाट न करें किम को पट्टा करे और किस को पट्टा न करे। इस सम्बन्ध में मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है कि वह मेहरबानी करके अपना पैसा लिये जाये या जो भी कायदे कानून है उन को बरते लेकिन वहाँ का तमाम इतजाम राजस्थान सरकार को दे दिया जाय जिस से कि कोई निविचन एपारिटी हो जोकि सब इतजाम करे। आज हमारे काश्तकार को बड़ी परेशानी का सामना करना होता है और अगर वह कोई पट्टा करना चाहता है तो उस को पता नहीं रहता कि वह किस के पास जाय पहले कस्टोडियन अफसर के पास जाय या सेटिलमेंट अफसर के पास जाय और इसलिये मैं चाहता हू कि काश्तकारों की इस परेशानी को खत्म किया जाय। न तो मेव काश्तकार को पता लगता है न रेभ्यूजी काश्तकार को पता लगता है और इस परेशानी और दिक्कत को रफ़ा करने के लिये कोई एक ऐसी निविचत एजेंसी बना दी जाय ताकि उन को अपना काम करवाने के लिये अलग अलग दौडना न पड़े और एक ही एजेंसी पर जा कर वह अपनी दर-हवास्त दे सकें और पट्टे वगैरह का मत्र काम पूरा कर सकें।

इम के अलावा यह जो प्रापरटीज सेल की जाती है उन के बारे में मैं यह कहना चाहता हू कि अड्डल तो यह होता है कि १०,००० रुपये में कम मालियत की जो जमीन है और जोकि शरणार्थी को एलाट की हुई है वह उन को दे दी जायगी और उन को मुआबिज में भर लिया जायगा।

लेकिन अमल में हम देखते हैं कि कुछ और ही हो रहा है। एक जमीन पर जिस पर कि शरणार्थी आबाद हैं उस को आप के आदमी लूले तीर पर नीलाम करते हैं और चूकि उन के पास उस को खरीदने के लिये काफी पैसा नहीं होता है इसलिये वे उम को खरीद नहीं पाते हैं और उन को उन जगहों से निकाल दिया जाता है। इस तरह के कितने ही केसेज भेरे नोटिस में आये हैं और उन्होंने दरहवास्तों भेजी है और मैं समझता हू कि वह दो, तीन रोज में उन नक-पट्टा भी जायेंगे। मैं चाहता हू कि पुनर्वासि मंत्री महोदय और उन का मन्त्रालय इस समस्या की ओर ध्यान दें और जो शरणार्थी उन जगहों पर आबाद हैं उन को इस तीर पर निकाल बाहर न किया जाय बल्कि उन जगहों और मकानों में जिन में कि वे आबाद हो, वे उन को दे दी जायें और उन की कीमत उन के मुआबिज से काट ली जाय।

श्री मेहर खन्ड खन्ना : मैं माननीय सदस्य का बहुत ही मशकूर हुगा अगर वह मुझे कोई ऐसा केस बतायेंगे जिस में कि एक एलैटिबन प्रापरटी जिस की कि कीमत १०,००० से नीचे हो, जिस का कि आकु-पेशन एथोगाड्ड हो और एलैटी उमे खरीदना चाहता हो वह उन को न दी जा कर उम प्रापरटी को नीलाम करने का हुक्म भेरे वहाँ से दिया गया हो ?

श्री पहाड़िया : मैं अपना भाषण समाप्त करने के बाद मंत्री महोदय को एक प्लाट का ही नम्बर नहीं बल्कि दो प्लाट्स के नम्बर दू गा जिन में कि ऐसा किया गया है और वह उन के बारे में जाच पढताल करवा सकते हैं।

अब प्लाट्स की नीलामी के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उम में बड़ी घपने-बाजी चलती है क्योंकि कोई अलग अलग मकान तो बने हुए हैं नहीं जिन की कि नीलामी की जानी है। प्लाट्स तो मफा चट जमीन पर

[श्री पहाड़िया]

होते हैं और ज्यादातर के तौर पर मैं आप को बतलाऊँ कि नबी मुहम्मद नं० १ प्लाट पर बहुसंख्यक किरायेदार आबाद हैं और नम्बर २ प्लाट पर इस्लामी मुहम्मद आबाद हैं अब जब कस्टोडियन मुहम्मद वाले सेल करने जाते हैं तो इस प्लाट्स के सेल में भी रिपब्लिश करती है और नतीजा यह होता है कि दोनों प्लाट्स को नक्राओ में एक ही प्लाट दिखा कर नीलाम कर देते हैं और उस को तफीमुहम्मद खरीदार को दे देते हैं। और वे बेचारे लोकल लोग जोकि उन प्लाट्स के किरायेदार होते हैं वे मुंह ताकते रह जाते हैं और उन की बेदखली की नीबत आ जाती है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप ने जो प्लाट्स की लिस्ट बनाई है वह अब पुरानी हो चुकी है और उस को फिर से रिवाइज करने की बहुत जरूरत है और उन की लिस्ट लोकल रेवाइज से टैली करनी चाहिये ताकि ठीक से पता चल सके कि कौन से प्लाट की नीलामी हो रही है और आज जो यह गडबड चल रही है वह बन्द हो।

अब करप्शन की तो बात ही क्या कहना। वहाँ के लोकल लोग और खास कर हमारे गरीब हरिजन भाई जोकि वहाँ पर अपनी जमीनो पर आबाद थे उन से सहरीरी सबूत मांगा जाता है कि वह बाऊँ में उन जमीनो पर आबाद होने के हकदार हैं। उन से कहा जाता है कि आप इस की तसदीक कराइये कि यह आप की जमीन है। अब आप ही समझ सकते हैं कि उन बेचारों के पास तसदीक कराने के लिये क्या रक्खा है? जो कुछ कागजात वगैरह थे भी वे भाग से जल गये या पानी में बह कर नष्ट हो गये। आज हरिजनों को यह कह कर उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है कि यह जमीन कस्टोडियन की है और कस्टोडियन को कह कर उस को नीलाम कर देते हैं इस तरह। इसके कितने ही केसेज

अबाधत में चल रहे हैं। अब हरिजन लोगों को इस के कारण बड़ी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले आप ने फ्रीसा किया था कि जो हरिजन लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन-को ही बाजिब तरीके पर दिया जायगा और पंजाब में आप ने शायद ऐसा किया भी है तो फिर राजस्थान में क्यों इस मुविषा से लोगों को बचित रक्खा जा रहा है? करप्शन की हद हो रही है और आप के कस्टोडियन के अफसरान जिस को मरजी चाहते हैं उस से कुछ ले कर उस को तो आबाद रहने देते हैं और बाकी लोगों को उन की जगहों को दूसरों को नीलाम कर के बेदखल कर देते हैं। इस तरह की धीगामुश्ती को रोकना चाहिये।

इस के साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे प्लाट्स हैं जिन को कि रेसीजस प्लाट्स कह कर आप ने छोड़ रक्खा है। अब मसलान् वहाँ पर कोई तकिया था, कच्ची कन्न बनी हुई थी लेकिन अब तो वहाँ पर खेत खड़ा है और आप ने ऐसी जमीनो की नीलामी इस बिना पर रोक रक्खी है कि यह रेसीजस प्रापरटीज हैं। अब मेरा कहना यह है कि अगर आप ऐसे स्थानों की नीलामी खुले तौर पर नहीं कर सकते तो आप उन को शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों या अन्य समाजोपयोगी संस्थाओं को दे सकते हैं। हम ऐसे प्लाट्स को पंचायतों को दे सकते हैं। अब उन जगहों में न तो कोई मंदिर नजर आता है न मस्जिद और तकिया वगैरह और मैं नहीं समझता कि उन की नीलामी क्यों रोकੀ जा रही है। सरकारी तौर पर उन जमीनो का इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई कारण मुझे तो नहीं दिखाई देता कि वे इस तरह बेकार पड़ी रहे। हम से पंचायतों और दूसरे मसलस जमीन की प्राये दिन मांग करते रहते हैं और हम इस तरह की जमीन उन पंचायतों, मसलस और सामाजिक संस्थाओं को ब ड

आसानी से दे सकते हैं और मुझे तो उस में कोई विषयगत मन्त्र नहीं आती है ।

मैं इतना ही निवेदन कर के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मेवात की समस्याओं को मंत्री महोदय धीमातिथीय हल करने का प्रयत्न करें ।

श्री मेहर बन्धु लामा : जो धार्मिक स्थान उन को नीलाम कर दें ?

श्री महाशय्या . मैं ने प्रश्न किया कि वहाँ पर कुछ इस प्रकार के धार्मिक स्थान बिलकुल बेकार पड़े हुए हैं । वह जमीन ऊबड़ खाबड़ हो गई है, मकान बगैरह कुछ नहीं हैं बिलकुल जमीन बेकार पड़ी हुई है और मंत्री महोदय मुझे यह कहने के लिये माफ़ करे कि लोग उन जगहों पर टट्टी व पेशाब करते हैं । मैं चाहता हूँ कि पैसे जमीनों को काम में लाया जाय ।

Mr. Chairman: Shri Bangshi Thakur. Hence forward, hon. Members should confine their remarks to ten minutes.

Shri Bangshi Thakur (Tripura—Reserved—Sch. Tribes): Mr. Chairman, Sir, Rehabilitation department is like a foreign body which has been made to thrust in the body of India at the cost of the refugees. Though it is temporary in nature, yet its colossal problems, multiplied by complicated day to day developments, seem to be not within easy reach of solution. In the year 1958-59, the total amount budgeted for rehabilitation is about 9 per cent of the total budgeted expenditure of the Government of India for the same year. This year also, if it has not exceeded the amount of the previous year, it has not been reduced remarkably. The position is that the government tax the people and the Rehabilitation Department tax the Government and, as a matter of fact, the investment gives nothing in return.

Sir, let me concentrate my attention to Tripura. I think no country in the world can be found out where the number of refugees has exceeded that of the local population. What is the position of West Germany, of which it is said that coming of refugees in that part is numberless and unceasing. There also the position is about 1 : 4; that is, the refugee is 1 and the local population is 4. But, in Tripura, we find that the local population has been outnumbered by the refugees. In the census of Tripura State in 1950 T.E. i.e., 1940 A.D. we find that the population of Tripura State was 3,82,450 but the number of refugees who are to be accommodated in Tripura is about 4 to 5 lakhs. The purpose of my showing the ratio here is to say that the refugee rehabilitation problem in Tripura is far more difficult than that of any other part in India.

Sir, Tripura is a hilly place. There are five off-shoots of Himalayan ranges which have passed through Tripura from the north to the south. Besides these ranges, there are numerous hillocks scattered almost all over the territory of Tripura. Yet, these are not all; vast areas are covered with dense forest; so, the ploughable plain land available in Tripura is quite inadequate to satisfy the demands of the refugees and the local peasants, who are landless. As far as transport and communications are concerned, Tripura is very backward and underdeveloped so no industry has been established there up till now which can be utilised for the economic rehabilitation of the refugees.

The local Administration has established some industries in Tripura but those are of a limited capacity, rather those cannot be categorised as productive establishments; and those did not come out of the boundary of experiments.

In view of the transport difficulties and in view of the fact that Tripura is nearly blockaded by Pakistan, the local Administration also could not advance

[Shri Bangshi Thakur]

beyond the limit allowed by the existing natural facilities in this direction. Moreover, the refugees are the inhabitants of plain areas but they are to be rehabilitated in hills, forests and tillas.

When the refugees came to Tripura first, they had been given doles first; then, they were asked to show that they possessed ploughable lands against the security of which housing and other loans could be given to them. It was impossible for them to show that they possessed ploughable lands. Who was going to give them lands? Moreover, they had no money to buy lands. Sir, the village head, the local officers also could not go against the rules. But, above all, it had been felt by all that the refugees must be kept alive. So, in papers it had been shown that such and such persons possessed such and such lands; and, following that process, they were given loans.

Now, what I want to say is, that if the situation permits the Government to give 5 kanis i.e., two acres of land to each of the refugee families, then, those who had been given lands or paper but did not get them in fact, should not be deprived.

There are other factors also. Some of the refugees had been allotted lands but when they went to occupy the same and began cutting the jungles, the real owners of the lands filed suits against them and some of them are still pending. The result was that the loans which they received had to be spent for litigation purposes. A fairly large number of refugees are yet to be given loans of various descriptions. The previous loans also, which had been given to the refugees, had been given in 5, 7, 10 or 15 instalments and so the loanees could not utilise the loan moneys in the direction they were meant for.

What about Raima Saima? As far as Raima Saima is concerned, if you could make your plan successful, then,

about 20,000 families, that is, one lakh persons could have been rehabilitated there and 80,000 acres of land could be reclaimed and utilised for rehabilitation purposes. Not only that; about 64,000 acres of very fertile lands could have been brought under regular cultivation and the yearly yield would have been at least 30 lakhs mds. of paddy. Had it been done, 80 per cent of the rehabilitation problems could have been solved and we could see Tripura self-sufficient in food. But, you could not do that.

When the hon. Minister says that he will close down the Rehabilitation Department in Tripura, within one year, that is, he will complete the work of rehabilitation in Tripura within the specified time, I also cannot but support him in the light of the huge amount sanctioned and spent and going to be spent.

But, let me ask him whether he has examined that the huge sums have been fully utilised to serve the purpose for which they were sanctioned or not. The money has not been fully utilised. So, the hon. Minister is not in a position to close down the Relief and Rehabilitation Department in Tripura within a year. Without economically rehabilitating the refugees he cannot do that. If he does, then, he will invite troubles from all sides. Under these circumstances, I would like to say that if all his efforts, endeavours and preparations are compared with the problems, which I have said colossal, then, it will be amounting to a pygmy hampering a giant.

So, I request the hon. Minister to consider the matter in its proper perspective and I request him also to form an Advisory Committee consisting of M. Ps. of both Houses, among others, which will study the rehabilitation problems in Tripura and submit its report to him.

Shri Anurobindo Ghosal (Uluberia):
Mr. Chairman, Sir, last day the hon.

Members who spoke on behalf of the truncated west had mixed feelings of happiness and unhappiness at the same time, happy because some of the problems had been solved and unhappy because still there were some works to be done. But, for the spokesmen of the East, they can have no flowers except stones.

Shri Mehr Chand Khanna: Except what?

Shri Anrubindo Ghosal: Except stones

This refugees problem is a long and vexed problem no doubt. But it is surprising that though about a decade is going to pass neither the State Government nor the Central Government has been able to tackle this problem to the satisfaction of both the refugees as well as the other persons.

Now, the condition of the camps is horrible and nobody who has not seen how these refugees are leading their lives will be able to imagine that I would request some of the hon. Members who advocate the cause of monkeys, cows and buffaloes to see how their fellowmen are living in these camps in West Bengal.

Sir, I do not like to go into the question of responsibility. The responsibility of rehabilitating them, the responsibility to assure them the right to lead a human life, and the responsibility of maintaining them lies with you, because you are responsible for readily agreeing to the partition of the country which could have been avoided as it is now given out in the writings of a national leader, Maulana Sahib. I shall give some statistics in order to prove the magnitude of the problem and also the inefficiency and incapacity of the Ministry. About 41 lakh refugees have so far come from East Pakistan out of whom 32 lakhs are in West Bengal. Out of 32 lakhs again who are in West Bengal, two lakhs are still in camps. Both the State and the Central Governments

took this problem light-heartedly and as a result of that there has been a miserable failure. Upto 1957 the only thing that the Central Government used to do is to grant a lump sum amount to the State and the State Government used to manage the whole affair. Up to 1957, the State Government only used to pay doles but it never tried to rehabilitate these refugees who are in these camps. A substantial portion of this rehabilitation money that was granted to the State Government again went into the pockets of the contractors and some of the persons whose forefathers were once the people of East Pakistan. Up to 1957, there was rarely a single morning when we did not come across a new rehabilitation scandal in West Bengal. The then Minister of Rehabilitation of my State is now an hon. Member of this House and if she likes she will be in a better position to tell these things as to why they were unable to tackle this problem properly from 1954. The Government began to send these refugees to the neighbouring States like Bihar, Orissa, U.P. and Madhya Pradesh in batches but within a short time there were mass desertions from all these camps. It is not because of any defects on the part of sister States but because of the absence of any plan or scheme to rehabilitate them there, because they were also forced to lead a camp life in those places in the other States and it is quite imaginable that if a refugee has got to lead a camp life instead of being rehabilitated he would naturally prefer the West Bengal camp to a mango grove of Betiah. I had the privilege of going to Betiah after the mass desertion to enquire as to what might be the reasons of this desertion. I found not a single desertion from this group of persons who were rehabilitated in the land in that area. That is not my opinion. The West Bengal Government has also admitted it on page 20 of their booklet.

'The desire of a Bengalee to live in West Bengal is appreciated

[Shri Aurobindo Ghosal]

and is understandable, but economic necessity does and should outweigh most considerations. What is necessary is that displaced persons who have left their hearths and homes should settle down contentedly and happily with an adequate living resources wherever they are. I do not believe that left to themselves displaced persons in camps would prefer to stay in West Bengal within an inadequate living facilities rather than go out for an adequate living. No question of using force arises. Even at the height of the agitations started in last March against movement of displaced persons to rehabilitation sites outside the State, displaced persons from camps did move out to such sites. Others from amongst them went before and some others after. No pressure was brought to bear upon them to leave. Recently several families of non-camp displaced persons left for Rajasthan for rehabilitation. All this indicates that displaced persons in camps would not, under proper leadership and guidance, be reluctant to go to any rehabilitation site outside the State which will offer them an adequate living."

From this it is proved that the West Bengal refugees are not unwilling to go outside but because of the want of proper areas in those refugee camps, there were mass desertions.

Shri Mehr Chand Khanna: When did the desertions take place?

Shri Aurobindo Ghosal: About three years ago. Besides the doles, a huge amount was given to the refugees as house-building loans. During the years 1956, 1957 and 1958, Rs. 850 lakhs was granted as rehabilitation loans to non-camp families out of which the house-building loan alone amounted to Rs. 700 lakhs. But I doubt if more than 25 per cent of these loans went into the pockets of the refugees themselves.

I would like to enumerate the difficulties in this connection. The loan was never based on the costing of the building in spite of the plans, etc. It was always less than that amount and it was a compromise amount between the claimed amount and the amount offered by the Government. Secondly, it was paid in dribbles and instalments and there was also generally delay extending to 2-2½ years. By that time the claimant is settled either in rented houses or in small houses built by him. Naturally when he got this loan it was of no use to him and it was spent for other purposes. Thirdly, the procedure was itself bad which encouraged corruption and I have rarely found a refugee getting Rs. 2,000 even if the loan granted amounted to Rs. 2,000. Lastly, instead of paying the amount in cash, the Government should have either built the house through the C.P.W.D. or some such agency or should have supplied the building materials in lieu of cash money. In that case, there was a chance of the loan being used for the proper purpose for which it was granted.

In 1957, in the Darjeeling conference the West Bengal Government agreed to absorb fifty per cent of the displaced families within the State. In July 1958, it has revised its position and has agreed to take the responsibility of rehabilitating 10,000 families within the State and the Government of India have now taken the responsibility of rehabilitating 35,000 families. So, the scheme of Dandakaranya came into lime-light. Government has announced that the camps would be closed in July 1959. Now, I would like to know from the hon. Minister as to what is the performance till now. Because, there is hardly three months' time. So far as I know, the Government has not been able to receive more than 500 families in Dandakaranya so far and the West Bengal Government has been asked not to despatch any more families to this place. Now, the State Government thought of absorbing 10,000 families by setting up 17 medium industries out of whom there

are seven cotton mills and a few rolling mills. Due to slump in the market, it will not be possible to set up these industries. I would like to know from the hon. Minister if any alternative industry has been selected.

As regards the reclamation of land, I submit that the Government is not prepared to accept the statistics of the report of Ishaque. Still from the crop survey report the available land for reclamation is 1.6 million acres. What steps have been taken to reclaim the land for the rehabilitation of the refugees?

Lastly, as regards Dandakaranya, the public are confronted with two sorts of stories. One sort of report says that parts of Dandakaranya are strewn with petals of roses and another story is that it is a veritable hell. I want to know the real facts from the hon. Minister about Dandakaranya and the possibility of the rehabilitation of the refugees within the target date of July 1959 and what steps are being taken to rehabilitate them in the industries of West Bengal and in the lands which are to be reclaimed within the State of West Bengal.

13 hrs.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : सभापति महोदय, मैं पुनर्वासि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उस काम पर जोकि उन के मंत्रालय ने किया है। लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ कठिनाइयाँ हैं जिन को मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ।

सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत से गावों में पुनर्वासि मंत्रालय की भूमि पड़ी हुई जिसे कोई विस्थापित भाई नहीं ले रहे हैं, और जिस पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया है। आपने पंजाब में हरिजनों को भूदान आदि बनाने के लिए जमीन दी है। मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से दिल्ली में भी आप हरिजनों को जमीन दें। पिछले दिनों आपने एक प्रश्न के उत्तर में

पंजाब के लिए यह स्वीकार भी किया था कि वह भूमि पिछड़े वर्ग के लोगों को और हरिजनों को दी जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी वही बरतवा किया जाये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नई कालोनी शील कुरंजा बनायी गयी है। मैं मालूम वह कालोनी किस विचार से बसायी गयी थी, किस इंजिनियर ने इस को बसाने का सुझाव दिया था। मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह कालोनी बहुत ही नीची जमीन में है। जरा सी बरसात होते ही वहाँ पानी उबलने लगता है।

इसके प्रतिरिक्त वहाँ के किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जब भी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के उस इलाके में जाता हूँ तो किसान लोग मेरे पास आते हैं और रोने लगते हैं। वह कहते कि हमें मुआवजा किस कदर कम दिया जाता है। उनको १०० रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता है जो कि दस नये पैसे प्रति बर्ग गज पड़ता है और जिन को उस जमीन पर बसाया गया है उनसे पुनर्वासि मंत्रालय ११ रुपये प्रति बर्ग गज के हिसाब से बसूल करता है। आप विचार कीजिये कि एक और तो विस्थापित लोगों से ११ रुपये प्रति बर्ग गज के हिसाब से रुपया बसूल किया जाता है और दूसरी ओर जिनकी वह भूमि है उन किसानों को दस नये पैसे प्रति बर्ग गज के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। यह असमानता बहुत अनुचित मालूम पड़ती है। आप उस पर विकास का खर्च भी लगा लें तो उसे आप साठे चार रुपये, पांच रुपये, साठे सात रुपये या ज्यादा से ज्यादा आठ रुपये प्रति बर्ग गज पर विस्थापितों को दें। किन्तु उनसे ११ रुपये प्रति बर्ग गज के हिसाब से लिया जाता है और जिस किसान की जमीन है, जिसका कि सब कुछ उजड़ गया है, उसको दस नये पैसे प्रति बर्ग गज के हिसाब से दिया

[श्री नवल प्रसाद]

जाता है, वह कहां तक स्वाम संगत है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनको इतना कम मुआबजा क्यों दिया जा रहा है और विस्थापितों से इतना अधिक क्यों लिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि वह इसका कारण बतायें।

जहां तक की तीन नई कालोनीज, श्रील कुंजा, तहार और रमेश नगर का ताल्लुक है, इन तीनों कालोनीज ने विस्थापितों को १०० बर्ग गज जमीन और ५२० रुपया की विस्थापित दिया गया था। हमारी बहिन डा० सुधीला नायर जो पहले दिल्ली राज्य के मन्टर पुनर्वास मंत्री थी, उन्होंने, सुनते हैं, कहा था कि जिस जमीन पर आपको बसाया गया है वह भूमि आपको मुफ्त दे दी जाती है और यह ५२० रुपया भी आपको मुफ्त दिया जाता है। किन्तु अब उन विस्थापित भाइयों से जिनके कि क्लेम है कहा जाता है कि तुम को पूरा रुपया देना होगा और उनसे रुपया वसूल किया जाता है और उस रुपये की वसूली में भी बड़ी असमानता है। किसी से १२०० रुपये वसूल किये गये, किसी से १३०० वसूल किये, किसी से १६०० वसूल किये गये और किसी से १८०० वसूल किये गये। मैं मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस तरह की असमानता एक ही कालोनी में, एक ही जैसे प्लॉट के लिए क्यों की जा रही है।

जिनके क्लेम नहीं है उनको ५३० रुपये की छूट दी गयी है। किन्तु जैसा कि मैं ने अभी बताया, जो जमीन दस नये पैसे प्रति बर्ग गज के हिसाब से ली गयी है उस पर अगर आप ५३० रुपये और भी लगा लें तो भी सरकार को लाभ रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बताने की कृपा की जाये कि यह लाभ क्यों है।

जहां तक इन कालोनीज का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में मैं ने बहुत से प्रश्न किये

और उनके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया, उन्होंने एक बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट दी, कि प्रत्येक तारीख को यहां बिजली पहुंच जायेगी, प्रत्येक तारीख को नल लग जायेंगे, प्रत्येक तारीख को सीवर जग जयेंगा प्रादि-प्रादि। किन्तु जे तिथियां निश्चित की गयी थी उनको तीन वर्ष बीत गये और अब पुनर्वास मंत्रालय बन्द होने जा रहा है, पर वह सब काम पूरा नहीं हो पाया है। मैं ने चार साल पहले एक प्रश्न किया था कि यह जो नई कालोनी श्रील कुंजा की है उसमें पानी भर जाता है। उसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि हम वहां पर एक पंप मगवाकर लगा देने और वह पानी बाहर निकाल दिया जाया करेगा। किन्तु मैं अभी थोड़े दिन हुए वहां गया था। वहां पर आज की तारीख तक तो कोई पम्प लगा नहीं है यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ और पानी वहां से नहीं निकल रहा है, नालियों का पानी सड़ता रहता है क्योंकि जमीन नीची है। तो मैं चाहूंगा कि यदि पम्प लगाना है तो वैसा कह दीजिये और अगर नहीं लगाना है तो वैसा कह दीजिये कि पम्प नहीं लगाना है, कोई इन्तिजाम नहीं हो सका है, या यह कह दीजिये कि हमने जो आर्डर दिया था वह कैसिल कर दिया है, ताकि जो आशा रूती है वह तो कम से कम न रहे।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। वह यह कि यदि आप इन कालोनीज का विकास नहीं कर सकते हैं तो आप कृपा करके दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को कहिये और उनसे कोई कैसला कर लीजिये, उनको जो कुछ भी आप डेवेलपमेंट चार्जस देना चाहें दे दीजिये, या चाहे न दीजिये, आप उन पर कोई नैतिक दबाव डाल दीजिये या कोई प्रादेश दे दीजिये ताकि उन कालोनीज में किसी न किसी तरह उन विस्थापित

भाइयों के लिए विकास हो जाये। मुझे आशा है आप यह करेंगे, और मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहता हूँ कि इस काम के लिए आपका वायदा है, और यह काम हो जाना चाहिए।

एक कालोनी आपने बनायी है कीर्ति नगर। 'उस कालोनी के लिए आपने एक कारपोरेशन बनाया था। उस कारपोरेशन का यह काम था कि जो ज्यादा पैसा दे उसको प्लाट दिया जाये। उसने प्रारम्भ में आठ रुपये प्रति गं गज के हिसाब से जमीन दी पर अन्त में उसका दाम ६५ रुपये प्रति वर्ग गज तक कर दिया। आप देखें कि भारी टेंडरों पर यह जमीनें दी गयी और विस्थापित भाइयों ने अपने ब्लेम और जेवर आदि बेचकर आपको पैसा दिया। लेकिन पिछले ६ वर्ष से वे निरन्तर प्रार्थना करते आ रहे हैं कि हमें पट्टा दे दिया जाये ताकि हम दिल्ली प्रशासन से ऋण ले सकें और अपने लिए मकान बना सकें जिसमें रह सकें, किन्तु उनकी इतनी प्रार्थना करने पर भी और उनके पूरा पैसा दे देने पर भी उनको कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा है जिसको वह से उनको ऋण नहीं मिल रहा और वे मकान नहीं बना पा रहे हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। इसमें प्रशासन का कोई पैसा खर्च होने का सवाल नहीं है। मैं देखता हूँ कि इस प्रशासन में ऐसी खराबी आ गयी है कि कोई काम हो उसमें देरी की जाती है। उस कारपोरेशन का यह काम था कि वह प्लाट बेच दे और उनका विकास करे और समाप्त हो जाये। उस कारपोरेशन ने तमाम प्लाट बेच दिये हैं और भूमि का विकास भी हो रहा है और वह विकास का काम सी० पी० डब्ल्यू० डी० को दे दिया गया है। इस तरह से कारपोरेशन का काम खत्म हो गया है। लेकिन पट्टे देने का काम अभी बाकी पड़ा है और इसलिए कुछ लोग अभी भी उसमें पिचके हुए हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुनर्वास मंचालय और पुनर्वास मंत्री महोदय से बार-

बार प्रार्थना की जा रही है लेकिन वह इस काम को सम्पन्न नहीं कराते हैं। ६ साल पहले जब कि हमारा

Mr. Chairman: Order, order. The hon. Member is giving details of individual grievances. It is not possible that he can finish all the grievances here on the floor of the House

श्री नवल प्रभाकर : इस बात को मैं छोड़ देता हूँ और अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कुछ मकान बनाए हैं, लेकिन वे अभी से टपकने लगे हैं, टूट गए हैं और गिरने वाले हैं। इस तरह के तो मकान बनाए गए हैं, लेकिन उन के लिए इतनी रकम धोपी गई है। स्वभावतः लोग देखते हैं कि हम से इतनी रकम ली जा रही है, लेकिन जो मकान बनाए गए हैं, वे गिरने वाले हैं। अगर सरकार कोई इस तरह की चीज को खरीदे, जो कि निकम्बी हो, तो उम के पैसे वह क्यों देगी? मेरा अनुरोध है कि इस विषय में एक्शन लिया जाना चाहिए। पटेलनगर, मोतीनगर और तिलकनगर में जो ऐसे मकान हैं, जो कि बिल्कुल अर्जर अवस्था में हैं और जो गिरने वाले हैं, उन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

मकानों की कीमतों में जो असमानता है, उस के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो डबल-स्टोरीड मकान हैं, वे बहुत थोड़ी जगह में बने हुए हैं, लेकिन उन की कीमत बहुत ज्यादा है, जब कि जो मकान २०० गज के प्लाटस पर बने हुए हैं, उन की कीमत थोड़ी है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस असमानता पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

कहने के लिए मेरे पास कई बातें थी, लेकिन समय कम होने के कारण मैं समाप्त करता हूँ।

श्री बुशीवाल (धम्बाला-रक्षित-अनुसूचित जातियां) - सभापति महोदय,

[श्री बुन्नीसाल]

आप ने मुझे दो सप्प कहने का अवसर दिया, उस के लिए मैं आप को बन्ववाद देता हूँ। मैं इस मंत्रालय और मंत्री महोदय को बुधवारकाद देना चाहता हूँ कि मंत्रालय ने बड़ा बड़ा काम किया है। इतने लोग यहाँ पर आए, उन सब को बसाना, उन को रोजगार देना एक बहुत बड़ा काम है। अगर देखा जाय, तो जो पाकिस्तान से आए हुए भाई हैं, वे हर मीदान में हर तरह से यहाँ के रहने वाले लोगों से भागे ही मिलते हैं। आज उन की हालत ऐसी है कि उन को पिछड़ा हुआ या धारणार्थी या दुखी नहीं समझा जा सकता है। *जितना काम इस मंत्रालय ने पाकिस्तान से आने वाले भाइयों के लिए किया है, उस के लिए वे भाई इस मंत्रालय के और खास तौर से मंत्री महोदय के हमेशा आभारी रहेंगे।*

इस मंत्रालय ने उन लोगों के लिए दो लाख दो लाख के करीब खान बनाए, कालोनी बनाई, जिन में उन को इन्तकारी वगैरह की और रोजगार की काफी मूलियत दी ताकि वे आबाद होने के साथ-साथ रोजगार भी रह सकेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने १३ लाख स्टुडेंट्स को फ्रीशिप स्टाइपेंडज और ग्रान्ट्स की शकल में मदद दी, जिससे पाकिस्तान से आने वाले भाइयों के अच्छी तालीम पा सकें। २६ हजार लोगों को उन्होंने टेक्निकल और बोकेशनल ट्रेनिंग देने का इन्तजाम किया। इस मंत्रालय की तरफ से कई होम्स और इनफ़र्मरीज भी खोली गई हैं, जिन में मोल्ड परसन्स और फन-एटैबल औरतें रखी गई और वहाँ पर उन को इतनी सुविधायें दी गई, जो कि उन को बरों में भी नहीं प्राप्त हो सकती थी। सर्बिसिज में भी पाकिस्तान से आए हुए दो लाख से भी ज्यादा लोगों को काम दिलाया गया।

इस के साथ ही मैं मंत्रालय का इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ कि मंत्री महोदय

ने हरिजनों को गाँवों में बंजनीने, जो कि उन के पास थीं, जिन पर वे काबिज थे, बहुत सस्ते दामों पर थीं। हरिजन उस के लिए इस मंत्रालय के आभारी रहेंगे। इस के साथ ही उन्होंने उन हरिजनों से रेंट हासिल करने के लिए काफ़ी सलूलियतें दी हैं, जिन की तरफ़ काफ़ी रेंट बाकी है और यह तय किया कि एक महीने का रेंट उन से एरियस के तौर पर लिया जाय। इस के अलावा इस मंत्रालय ने तकरीबन पचास हजार मकान, जिन की लागत तकरीबन एक करोड़ रुपया है, हरिजन को पंजाब में करस एरियाज में दिए हैं। *मंत्रालय ने उन को बीस रुपए में मकान और दस रुपए में साइट दी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि शहरों में भी बहुत से हरिजन हैं, जो कि अपने झोपड़े बना कर या इन्कुरै प्रापर्टी में रहते हैं और वे सैकड़ों सालों से ऐसे रह रहे हैं बड़ी तादाद बीस, तीस पचास सान से ऐसे रह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय उन को भी मकान और प्रापर्टी नोमीनल प्राइसिज पर देने की कृपा करेंगे।*

पंडित ठाकुर बाल भार्गव (हिसार) :
हिसार में दी है।

श्री बुन्नीसाल : मैं स के लिए कह रहा हूँ। अगर हिसार में दी है, तो यह बड़ी खुशी की बात है। दरअसल अगर देखा जाय, तो हरिजन लोग पैदाशही रेफ़्यूजी हैं। उन के पास जमीन नहीं है। उन को डिस्प्लेस किया कहें, वे तो बिदाउट प्लेस हैं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय फ़रारखदिली से काम ले कर उन को यह शहरी जमीन व मकान देने की कृपा करेंगे।

जो मुसलमान गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और अलवर से चले गए थे, वे काफी तादाद में वहाँ से वापस आए। मंत्री महोदय और इस मंत्रालय ने उन को आबाद किया और उन की जमीन और

मकान वापस किए। यह भी उन्होंने सराहनीय काम किया है। इस के लिए मैं उन को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकता हूँ।

इस सबन में रीहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ स बर्ड पार्टी क्लेम्स का बादा १९५४ में किया गया था। बहुत सारे लोकल लोगों का कर्जा उन मुसलमानों की तरफ था। बहुत सारे जो कि यहां से चले गए। अगर वे यहां होते, तो इन ग्रनलेक्चोर्ड डेट्स को उन से बसूल किया जा सकता था, उनकी जायदाद से बसूल किया जा सकता था। लेकिन बूकि वे चले गए और उन की जमीन यहां रह गई और कस्टोडियन ने उस पर कब्जा किया, इस लिए वह कर्जा डिपार्टमेंट को उन लोगों को देना चाहिए क्योंकि यह उस का भ्रजलाकी फर्ज हो जाता है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप ने पहले ही मझे कह दिया है। एक बात और कह कर से बैठना चाहता हूँ। दडकारणय स्कीम ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी धक्की है और इस के लिए मैं मंत्री महोदय और इस मंत्रालय को बधाई देता हूँ।

धत: मैं यह प्रार्थना फिर करना चाहता हू कि शहरों के मकान भी हरिजनों को दे दिए जायें।

श्री० रजवीर सिंह (रोहतक)
दे दिए हैं।

श्री बुलीवाल: इस रिपोर्ट में तो नहीं है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना कि जो शहरी जायदाद हरिजनों के कब्जे में है, वह उन को देने की कृपा करेंगे।

Shri Dasaratha Deb (Tripura): Mr. Chairman, I shall be very brief

because I have to finish within five minutes. Generally, the work of the Rehabilitation Ministry is not satisfactory; rather, I should say it is very unsatisfactory. But Shri Mehr Chand Khanna more than once made a statement regarding the satisfactory rehabilitation work in Tripura. I do not agree with him.

In Tripura generally the refugees fall under two categories. One category consists of those refugees who came to Tripura before 1954 and the other category consists of those refugees who came after 1954. The refugees who came before 1954 were given rehabilitation benefits and loans, etc., on a scale which is much lower than the scale at which the new refugees are being paid. It is less than Rs. 1,000 per family. This payment was also made in instalments with the result that most of the money could not be given for the peasants for production purposes and that is why almost all the refugees are now under starvation conditions.

I am giving information of a very tragic incident now. Very recently in Pandhabpur colony, two refugees died of starvation after starving for more than seven days or so. Their names are: Nareesh Day and Nikhil Ghosh. I want the Rehabilitation Minister also to collect the information about them and I would also request him to evince interest in this and see that some relief is given to the inmates of those areas because those people are suffering. Further, the price of rice is more than Rs. 32 per maund in all those areas. The refugees and other people were not given ration cards because they do not possess *adda* receipts. I request the hon. Minister to look into this matter.

Another point to which I would like to draw the Minister's attention is this. Some 108 refugee families of Pandhabpur and some other areas have already submitted a memorandum to the Minister demanding a second set of loan and also increased

agricultural loan, but they have not been given those facilities. Very recently some 19 refugees have started a hunger-strike at Agartala at the premises of the rehabilitation office. Now the number has increased to 31. They started the hunger-strike on the 7th April, 1959 and they are still continuing it. Their demand is simple. On one occasion, the Director of the Rehabilitation Department of Tripura said that they realise the justness of their cause, but he expressed his inability to do something for them because, if he gives them some more loan, then he has to give the same facility to 60,000 families like that. But Mr. Khanna can do that job, because if their demand is just, simply because it has to be given to some more persons also, he should not rule out that possibility. I expect he will say something about the 31 persons who are on hunger-strike.

13.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Another point is with regard to the realisation of the loan money. Loans were advanced to the refugees, but for the last two years, the Tripura people have been suffering from shortage of foodstuffs. This year there was heavy loss of foodgrains due to draught, floods, etc. That is why in every part of Tripura, the price of rice is very heavy; it is Rs. 32 and in some places Rs. 40 per maund. So, the refugee is not in a position to pay that loan. So, I request the Minister to postpone the realisation of loans from the refugees for this period.

Regarding Raima Sarma scheme, I am told about 80,000 or more acres of land will be available. At one time the rehabilitation department had some plan to reclaim that land for rehabilitation purposes. But now it seems that either the scheme is abandoned or it is not being pursued. So, I request the Minister to pursue that plan.

Regarding demarcation of land, lands were allotted to the refugees, but they are not properly demarcated. So, disputes arise sometimes and the refugees have to spend money over litigation. At least, if any dispute arises regarding the land allotted by Government, the litigation cost must be borne by the department itself, because it arises not due to the fault of the refugees, but of the department itself.

Regarding the Sumanachara colony, mostly refugees were settled there some two years ago. But there is little scope to get plain land nearby for the refugees. So, they have to remain in land which is unfit for cultivation, with the result that they are living in starvation conditions. It was expected that they would be paid the reclamation cost two years before, but the cost has not been given to them even now. That is the cause of the whole trouble.

In Kalapani-Mohanbhog, in Sonamura, some 15 drones of land were requisitioned by the refugees, but the land was already occupied by tribals for more than 20 years before. They got that land by agreement with the Jotedars and they have been cultivating that land. But after this acquisition those people are asked to quit that land. I think it is very unfair to the people who have been already occupying that land. So, I request the Government that before they acquire some land, they should at least see whether the land belongs to such people who will be thrown out of employment after the acquisition. If the land belongs to some zamindars or jotedars, we have no objection and we will press the Government to acquire that land. But poor persons who own only 4 or 5 kanis of land should not be asked to quit that land merely because some people are to be rehabilitated there.

Then, recently 135 Class IV employees of the rehabilitation department

at Agartala were asked to draw their salaries at a lower rate. Since 1956, they have been receiving salary at Rs. 40 per month, but suddenly they have been asked to draw at Rs. 20 per month only. They were told that if they did not accept the lower rate, they would be treated as discharged from service, no further notice would be served and that was the ultimatum. I ask Mr. Khanna, why are they so unkind to class IV employees? Has he made any reduction in the salaries of big officers like Secretaries, Directors, Deputy Directors, etc., who have been receiving more salary? Why have the Class IV employees been chosen for reduction of salary? I ask him to review this matter. Their salary should not be reduced like that.

I hope Mr. Khanna will reply to all the points I have raised.

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर-रक्षित-अनुसूचित जातियाँ) उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि पंजाब के जो लोग हैं और दिल्ली के जो लोग हैं, जो मैम्बर हैं. उनको बोलने के लिए ज्यादा मौका दिया जाता है लेकिन जिन की हालत बहुत खराब है, उनको मौका नहीं दिया जाता है। पंजाब और दिल्ली वालों की हालत अच्छी है और उनको मौका भी मिलता जाता है लेकिन

श्री नबल प्रभाकर : यह विस्थापितों का मामला है।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : आप बीच में न बोलिये। मैं, जब भी आप बोलते हैं, कभी आपके बीच में नहीं बोलती हूँ। दिल्ली वाले हमारे जो काम हैं, वे होने नहीं देते हैं, और चाहते हैं कि उनके जितने काम हैं वे हो जायें। वे हमको बोलने में नहीं देना चाहते

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो सामोस बैठता हूँ। आप बोलिये और मैं सुनूंगा।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करती हूँ कि पुनर्वासि भेनी महोदय को देहातों में जा कर वहाँ का दौरा करना चाहिये। वहाँ पर वह कमी नहीं जाते हैं, वहाँ वा वह कमी दौरा नहीं करते हैं। दिल्ली में ही वह इशिक रहते हैं। दिल्ली की हालत को ही अच्छा बनाने की वह फिक करते हैं, उस जगह की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पर कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली में अच्छे मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, हरिजनों की भी अच्छी हालत है, वे भाई रोटी खाते हैं लेकिन उस एरिया की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जहाँ की हालत खराब है। हमारे मध्य प्रदेश में जो विस्थापित भाई आए थे उनकी वही हालत है जो कि १९४७ और १९४८ में थी, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। उनके लिए कोई पक्के मकान नहीं बनाये गये हैं। उनके पास जो टूटी फूटी झोंपड़ियाँ हैं, उनके ऊपर छप्पर पड़े हुए हैं, और बरसात के चार महीने उनके हाथ देया हाथ देया करके गुजरते हैं। विस्थापित भाई जहाँ जाकर बसे हैं वे हैं सागर, दमोह, बीना, कटनी इत्यादि और इन जगहों पर आप कमी गये भी नहीं हैं। जब भी कमी मैं वहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए, रचनात्मक कार्य करने के लिए जाती हूँ। वे लोग कहते हैं कि आपके चुने जाने से क्या फायदा हुआ, आप कभी यह आवाज भी नहीं लगाती हैं कि पक्के मकान ही इन लोगों के लिए बनें। दिल्ली के शरणार्थी तो हलवा पूरी खाते हैं, लेकिन वहाँ के भाइयों को बना खाने को भी नसीब नहीं होता है। वहाँ पर उनकी हालत नाजुक है।

वहाँ के लोग बार-बार मुझ से कहते हैं कि कुछ तो कहो। वे कहते हैं कि तुम कांग्रेसी जानती नहीं हो इस बातसे बोल भी नहीं सकती हो। मैं उनसे कहती हूँ कि हिन्दी तो जानती हूँ और बोल भी सकती हूँ। मैंने कई बार सदन में आप से कहा कि यहाँ पर कोई बात भाती है

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

तो इंग्लिश में आती है हिन्दी में नहीं आती है। अगर हिन्दी में भाये तो जो लोग हिन्दी बोलते हैं, जिन को इंग्लिश समझने में अड़चन होती है, वह भी उस को समझ सकें और बाहर वाले भी जिन्होंने हमें चुन कर भेजा है वह भी समझ सकें कि उनके लिये कुछ कहा गया है। इसी लिये हमारे भाई पार्लियामेंट में हिन्दी नहीं बोलते कि अगर वह हिन्दी में बोलते हैं तो हमारे पत्रकार लोग उनके बारे में एक शब्द नहीं लिखते। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो लम्बी चौड़ी स्पीच निकलती है। हमारे यहां के लोग हम से कहते हैं कि वाई हमारे लिये कभी कुछ नहीं बोलती, बोलती तो अखबार में न आता। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि जैसे यहाँ सब चीजें अंग्रेजी में आती है उसी प्रकार हिन्दी में भी आनी चाहियें और जिस क्षेत्र से ज्यादा मेम्बर चुन कर आते हैं यानि: बेदातो से, उन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : भाज वह जरूर लिखेंगे।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : नहीं, यहां मेरी बात नहीं है। मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह जनता की भलाई के लिये बालना चाहती हूँ, अपनी बड़ाई के लिये नहीं। जिस जनता ने हमें निर्वाचित कर के भेजा है उस के लिये कहती हूँ। अगर मैं अपनी बड़ाई के लिये कहूँ तो मुझे बैकुंठ में भी जगह नहीं मिलेगी। जो सेवा करे वह उस के लिये अपनी बड़ाई करे तो यह ठीक नहीं होता। हम तो जनता के सेवक हैं। मेरा पुनर्वासि मंत्री से प्रार्थना है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां शरणार्थियों की नाजुक हालत है उसे उन को देखना चाहिये। वैसे तो शरणार्थी लोग खेती करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे तो ब्यापार में ही निपुण हैं। ब्यापार में बड़े अच्छे हैं। जिन क्षेत्रों में शरणार्थी गये हैं वहां के व्यापारी रोज हैं, वे कहते हैं कि जब के शरणार्थी आये हैं, हमारा व्यापार खराब हो गया है। व्यापार में वे शरणार्थी लोग लगे

गये हैं, लेकिन कोई शरणार्थी जमीन नहीं जोतता है।

श्री० रघुबीर सिंह : पंजाब में जोलते हैं।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : पंजाब का प्रदेश बड़ा अच्छा है, वहां नहरें हू, पानी है, तमाम अच्छी चीजें उन को मिली हुई हैं, दूसरों को नहीं मिली। जब हमारे भाई बोलते हैं तो पंजाब की बात कहते हैं, यू०पी० की बात कहते हैं। पंजाब और यू० पी० के अन्दर नहरें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, सभी बातें हैं। लेकिन कुछ हम लोग हैं जो कि भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। पानी बरस गया तो फसल हो गई, नहीं बरसा तो खाल हो गई और लोग भूखों मरने लगते हैं। हमें ऐसी परिचाज को भी देखना चाहिये। जब आप बात कहते हैं तो पंजाब और उत्तर प्रदेश की। इस लिये मेरी प्रार्थना है, कि उन को ऐसी जगहों को देखना चाहिये जहां की हालत खराब है, जिन के लिये खाने को चना भी प्राप्त नहीं होता। जहां पर बैकुंठ बना हुआ है उसी को और बैकुंठ बना दिया जाता है। इस लिये मैं पुनर्वासि मंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप दौरे कीजिये और ऐसी जगहों को देखिये जहां की हालत बहुत खराब है।

भाज शरणार्थियों को सिन्धी पढ़ाने की बात हो रही है, उस को आप को देखना चाहिये।

श्री बजरंग सिंह (फिरोजाबाद) : वह तो भव जा रहे हैं, बीरा क्या करें ?

श्रीमती सहोदरा बाई राय : हिन्दी स्कूल खोलिये, हिन्दी पढ़ाइये। जहां पर सिन्धी लोग हैं वह शरणार्थी हैं, वह सिन्ध से चले आये आप उन को सिन्धी क्यों पढ़ाते हैं ? हिन्दी पढ़ाइये। आप उन के पास जाइये तो सिन्धी बोलते हैं। वस खाल हो गये

लेकिन अभी वह हिन्दी सीख नहीं पाये। आप कुछ ऐसा इन्तजाम कीजिये कि हिन्दी बालू हो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हिन्दी बालू हो, दूसरी तरफ जब आप सबन में आते हैं तो एज् और गोज् सिवा कुछ कहते ही नहीं। कोई कहता है कि हिन्दी बोलो, तो अंग्रेजी में कहेंगे कि ब्लडी फूल है, अगर हिन्दी बोलने वाला अंग्रेजी में बोले ता कहेंगे बेरी गुड। ऐसा नहीं होना चाहिये। ऐसा रखिये कि हमारे सदन के सारे लोग उस की कार्रवाई को समझ सकें और बेहात की जनता तक वह सारी चीजें पहुंच सक। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप इस के लिये उचित कदम उठायें।

जहां जहां शरणार्थियों के लिय अफसरों ने मकान बनवाये हैं उन में बैठने तक की जगह नहीं है। पैसा तो उसमें बहुत लगा, लेकिन पता नहीं वह पैसा किस की जेब में गया या क्या हुआ, पर जो भी मकान बने हैं वह इतने खराब हैं कि वहां पर कोई बैठ नहीं सकता है। मकान ऐसे होने चाहियें कि उन में शरणार्थी लोग अपनी कैमिलीज के साथ रह सकें।

अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि यहां पर जो भी कार्रवाई हो वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हो और उन लोगों को बोलने का मौका ज्यादा मिलना चाहिये जिन की हालत खराब है। पंजाब वालों को आप समय कम दिया करे। उन को धाखिर इस की क्या जरूरत है ?

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Could I have five minutes?

Mr. Deputy-Speaker: Yes.

Shri S. M. Banerjee: I wanted to speak on many points. But, unfortunately I have been given only five minutes. So, I will confine myself to a few important questions. My first question is: what is the Rehabilitation Ministry doing about the

scandal which is going on in auctioning? The other day there was a demonstration of 4,000 homeless persons who were lathi-charged. I do not want to mention anything about it. But the object for which they led the demonstration is a matter which should deserve the sympathetic consideration of the Rehabilitation Ministry. My information is—it may be wrong; in which case, I would like to be corrected—that there are certain touts who are in league with certain high officials who remain present at the time of auction simply to raise the value of the property with the result that a poor man who wants to have some property again; his claim gets only one room tenement though he may actually be entitled to a two-room tenement. So, there is a racket going on and, therefore, I want a specific answer from the hon. minister as to what action has been taken, or is being taken, to stop such things.

Then I come to my second point about auction. It was brought to my notice that on 19th March this year a notice was pasted on 7, Jantar Mantar Road—I am not sure whether it is 7 or 17; All India Congress Committee offices—that this property was a sort of evacuee property and it was being auctioned the next day, that is, on 20th March, 1959. I was surprised to know that. I was told by those who are staying in the out-houses of that particular building that this notice was pasted without informing anyone and that this property was going to be auctioned. In this very House I wanted to ask a Short Notice Question, which was disallowed, I do not know on what basis. I want to ask the hon. Minister whether the A.L.C.C. office building is an evacuee property and whether its valuation is nearly Rs. 14 lakhs and whether there is an attempt being made by some people to auction that property at a very low price without inviting any bidder to bid for that property.

Shri Mehr Chand Khanna: How can we auction a property at a low price?

Shri S. M. Banerjee: I do not know; it is for you to answer, whether first of all an attempt was being made....

Mr. Deputy-Speaker: Where were those touts gone?

Shri S. M. Banerjee: I do not know where the touts have gone. I do not belong to Delhi. Otherwise, I would have got those touts.

Mr. Deputy-Speaker: But you have just said that.

Shri S. M. Banerjee: This is a property where no tout is required. It is a deal. Therefore, I want to know whether any attempt was being made, whether a notice was pasted on the 19th March without giving information to the displaced persons that it is going to be auctioned on the 20th, but it was stopped and, if so, for what reasons.

My third point is about the claims. There are certain agencies—I do not know but I think they are unauthorised agencies—who are purchasing the verified claims at a lower rate, 50 per cent or 60 per cent of the value, and they say "We will give you cash money". I have myself received a letter—unfortunately, I did not bring it today—in this matter. There is some agency like this in Bombay. They have got their own people in Delhi. If a man wants cash immediately, these agencies pay a reduced amount. So, there are some agencies working in this line and they have got their agencies throughout the country. I want to know what steps are being taken to stop this agency from purchasing the verified claims by taking advantage of the poverty of the poor displaced persons.

Then I come to the fourth point. The hon. Minister has stated that a decision has been taken to evacuate the Purana Qila residents. Because of the history of the Purana Qila residents, I think it deserves sympathetic consideration from the hon. Minister. I do not know the reason, but when-

ever the hon. Minister replies to any Question or Short Notice Question or Calling Attention Notice, he does it with the vengeance against the Purana Qila residents. I was told that Jangpura is required for the Defence Ministry. I do not know whether that is a fact; that may be a fact, as the hon. Minister has said that. They want that land. So, these people were given some houses and some properties in Lajpatnagar. He says that Lajpatnagar is very close to Purana Qila. I do not know much about Delhi, but my information is that it is more than 2½ miles. The Purana Qila residents settled themselves in 1948. They did not take any loan from Government. They have spent nearly Rs. 60,000 on them. I have seen those tenements.

Shri Mehr Chand Khanna: The hon. Member is misquoting me. Only two days ago in reply to this Question I said—and you, Sir, were also in the Chair—that the land that is wanted or desired by the people of Purana Qila is only a few furlongs away from the place where I propose to allot them lands. I never said that this is the distance between Purana Qila and the land in Lajpat Nagar.

Shri S. M. Banerjee: I am sorry. I may not be correct but I never misquoted you. I quoted you correctly. All these things I cannot say in five minutes.

An attempt should be made to rehabilitate them. I think the Purana Qila people have got a case and I would request him to appoint a team from among the hon. Members of this House to ascertain whether the action taken by the Rehabilitation Ministry in rehabilitating these persons is correct or not. I simply want to elicit certain principle. My case is that the Purana Qila people have a strong case and it is the Rehabilitation Ministry, who somehow or other are wild about the Purana Qila people. Now,

the hon. Minister said that their case will be dealt with by the Scientific Research Ministry. You cannot convert a displaced person into a monument. They are still living persons and they must be treated sympathetically. This is my submission. I hope the hon. Minister will reply to all my three or four points and will try to convince not only me but also the House.

Pandit Thakur Das Bhargava: May I have one minute for this very question of Purana Qila people?

मेरी श्रद्धा से गुजारिश है कि पुराने किले के रेप्यूजीज के रिहैबिलिटेशन के बारे में मिनिस्टर साहब बाद में फैसला करें। मैं उनसे आज उस बारे में फैसला नहीं चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि आज भ्रमी वह उसके बारे में जवाब दें। मैं खुद बोलना चाहता था लेकिन वकत नहीं था। लेकिन मैंने इस बारे में उनसे वरब्बास्त की हुई है और मैं चाहता हूँ कि जो उनका केस है वह फिर मिनिस्टर साहब के सामने रैब्यु के लिए रक्खा जाय। इनको जो मिनिस्ट्री आफ कलचरल एफेयर्स के सुपुर्द किया है तो वह तो तेल ही निकालना जानते हैं और यह तो उन रेप्यूजीज का तेल ही निकाल देंगे या मोन्यूमेंट बना देंगे और मैं तो चाहता हूँ कि इनका मामला उसी रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री और मंत्री महोदय के सुपुर्द रहे जिन्होंने कि उनकी बुरे समय में हर तरह से मदद की और जब वहाँ पर तूफान आया तो वहाँ जाकर उनकी मदद की। वे ही उनके बारे में फैसला करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब उस बारे में ठीक और माकूल फैसला करेंगे। मेरे लायक दोस्त को जो यह ख्याल है कि बजीर साहब जब भी पुराने किले के रेप्यूजीज की बात बोलते हैं तो बेनबेंस से बोलते हैं, दुस्त नहीं है और उनके ऊपर ऐसा इन्जाम लगाना नामुनासिब है....

उपाध्यक्ष महोदय : यह नामुनासिब ही नहीं है बल्कि इससे उन लोगों के कौच को

जिसके लिए कि वह प्लीड करते हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं होता, नुकसान ही हो सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आज उस बारे में कोई जवाब न दिया जाय। मैं चाहता हूँ कि सारा केस दुबारा मिनिस्टर साहब के सामने रक्खा जाय और मुझे उम्मीद है कि उनके हाथ से ठीक और माकूल फैसला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या भी मंत्री महोदय से अपना प्रश्न कर लें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि पुराने किले में रेप्यूजीज के लिए जो क्वार्टर्स बने हुए हैं उनको मैं समझती हूँ कि बने हुए शायद १० वर्ष हुए होंगे। ईंट, चूना और सीमेंट से आखिर यह मकान बने थे और जब इन पक्के मकानों की यह अवस्था है कि वे तूफान आने से बह पड़ें तो फिर कच्चे मकान और झोंपड़ियों का तो कहना ही क्या। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जवाब मुनना चाहूँगी कि आखिर यह क्या बजह है कि वे इतनी जल्दी गिर गये जब कि हम देखते हैं कि पुराने पक्के बने हुए मकान कितने ही वर्षों १००, १०० वर्षों से खड़े रहने हैं। मैं चाहती हूँ कि मंत्री महोदय इस बारे में जांच करें कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। किसने एस्टिमेट्स बनाये थे, किस ठेकेदार को इन क्वार्टर्स को बनाने का ठेका दिया गया था और इनमें कैसा मैटेरियल लगाया गया आदि और जांच करके हाउस को इस बारे में पूरे डिटेल्स में बतलायें।

Shri Mehr Chand Khanna: Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is about four years now that I was invited by the hon. Prime Minister to take over the portfolio of this Ministry. As far as the western region is concerned, substantial progress and substantial results had been achieved in the field of

[Shri Mehr Chand Khanna]

rehabilitation and there were only two major problems which remained then which needed attention. One was the formulation and the implementation of the compensation scheme and the other was our negotiations with Pakistan in regard to urban immovable property and movable assets.

As far as the eastern region was concerned, the position was extremely fluid. Heavy exodus was taking place from East Pakistan and unfortunate Hindus who had lived there since generations were being pushed out at the rate of about 1,000 persons a day. Under those circumstances you will agree with me—and the House will also agree with me—that either to have formulated a plan or to have laid down targets was entirely impossible. But the conditions became stable two or three years after, that is, in the beginning of January, 1957 and we took some tangible steps in the eastern region as well to come to grips with the rehabilitation problem. When I talk of the eastern region and when I talk of West Bengal I also take into consideration the two neighbouring States, namely, Tripura and Assam, because of the 42 lakh persons, who have come from East Pakistan into India, about 32 lakhs are in West Bengal and of the remaining about nine lakhs in Assam and Tripura and about a lakh spread over the States of Bihar, Orissa, U.P., Madhya Pradesh et cetera. Our total population of displaced persons in the country today is nearly 90 lakhs I do not think any country, in the difficult we were placed in and more so immediately after the partition of the country, has ever been faced with such a stupendous and colossal problem. Of these 90 lakhs, about 47 lakhs are in the western region and about 42 lakhs, as I have just now stated, in the eastern region. As the problems in both these regions are practically dissimilar, though they are displaced persons—one has come from West Pakistan and the other from East

Pakistan—I propose to divide my observations or my remarks into two separate parts—one relating to the western region and the other to the eastern region. I shall take up the western region first.

As I stated just now, the two main problems were, firstly, the formulation of the compensation scheme and secondly negotiations with Pakistan. The compensation scheme has been one of the greatest achievements of this Ministry. I do not want to take any credit for it. The credit goes to the Government of India to the country and this House. Of the countries in the world where the refugee problem has arisen, in no single country in the world compensation has been given for any losses sustained on account of property by the migrants from the original country to the country where they have gone and taken shelter. This is the only country in the world where the biggest refugee population has come and taken shelter. This is the country which has given them compensation in spite of the heavy financial difficulties. We have been to many countries of the world and have taken loans but not one penny's worth of help has either come to us or has been received by us from any single country in the world for the rehabilitation of these unfortunate persons who have come from East and West Pakistan. Up-till now we have spent nearly Rs 330 crores on the rehabilitation of displaced persons and my work in the eastern region is still continuing. Every bit of it, every penny of it has been found from the General Revenues of this country. I said that this compensation scheme has no parallel in history. This compensation scheme had to be formulated after very careful consideration and thought and I would be failing in my duty if I do not take this opportunity of paying a tribute to a number of friends, whether inside this House or outside, who devoted not days but months in helping us in the formulation of that scheme. That scheme has

its two parts. One is the rural part of it and the other is the urban part of it. As far as the urban part is concerned, we have in the compensation pool assets to the extent of Rs. 185 crores. The number of persons who have to receive compensation, I think, is about 4,72,000.

This scheme was formulated and announced in June 1955 and the rules were passed by this House and the Upper House somewhere towards the end of September, 1955. I then stated that I shall try and do my best to implement this scheme in the shortest possible period and I laid before myself a target of 1 lakh cases a year. I am glad to say that we have been able not only to reach that target, but to exceed it. The figures given by my hon. friend Shri Ajit Singh Sarhadi, the day before yesterday, in the House, I am sorry to say, do not give a very clear and authentic picture. The number of persons who have been paid compensation till the end of February, 1959, according to my calculation is 4,00,735. He gave the figure of 289,779. But he conveniently omitted two figures. One is the figure of 57,719 who have been paid final instalment. I am not taking into account the number of 79,000 who were paid compensation under the interim scheme. I am only taking into consideration or account 57,719 persons who have been paid final compensation. In fact, we have done this work twice over.

Shri Ajit Singh Sarhadi: May I say....

Shri Mehr Chand Khanna: May I carry on? You may ask questions later.

I am not taking the figure of 79,109 to whom we paid interim compensation. Then, we had to re-open taking the figure of the interim compensation and the final compensation together. I am only taking the figure of final compensation. The figure is 57,719; 53,273 persons have been issued

statements of accounts. Many hon. friends in this House, perhaps, do not appreciate what I mean by a statement of account. A displaced person, who has filed compensation application and whose claim has been verified is entitled to the payment of compensation to him. According to our first idea, he should have been paid compensation through evacuee property in lieu of the property that he left in Pakistan. But, taking the condition of some of the priority categories, widows, old men, people suffering from T.B., cancer, etc.—we created 17 priorities and to these priorities, though they were entitled to an evacuee house left by a Muslim in India in lieu of the House left by him in Pakistan, we gave them over Rs. 50 crores hard cash in the shape of compensation. That was only for these priority categories. The rest of the people were to receive their compensation through the property, whether Government built or evacuee, which forms part of the pool. It was not for me to go to Sardar Ajit Singh and ask him, will you come to me and settle your account. It was for him to come to me. What I have done in these 53,000 cases is that I have finalised their cases and given them chits, given them certificates, given them statements of accounts: here you are, I have finalised your case; auctions are being held all over India every day; I do not want to allot you property through the backdoor; I do not want to allot you property through negotiation.

I am sorry to say, charges were made of corruption against my Ministry. I do not think I am immune or my officers are immune from corruption. It is a relative term. But, I can say

Shri Braj Raj Singh: You can say something of yourself.

Mr. Deputy-Speaker: He is saying.

Shri Mehr Chand Khanna: I am the head of this Ministry. If any of my officers are corrupt, I am also corrupt,

{Shri Mehr Chand Khanna}

I take full responsibility for their actions. We have been dealing with a scheme of Rs. 185 crores. We have given in relief and rehabilitation up-till now Rs. 330 crores. Minor references are made here and there. But, I propose to invite every one sitting there that if they come across a single case, let it be referred to me and I promise to look into it. I give this assurance to the House that if any cases have come to our notice, we have looked into them. If any case is brought to my notice, it shall be looked into. This Ministry is to give relief to the displaced persons. This Ministry is charged with rehabilitation. Some of our friends—I do not say they are in this House—whose main ideology in life whether here or somewhere else has become political exploitation of the displaced persons,—that is not my policy.

We have given compensation to nearly 4 lakh displaced persons. The total number now that remains is about 70,000. My average output is over 10,000 cases a month. In fact, this year, we have given compensation to 150,000 persons. Out of 4 lakh cases that have been disposed of, in 1958-59, we have disposed of 150,000 cases. That is a very brilliant record for any Ministry or for any set of officers who have to work under very difficult conditions. In this Ministry, you will realise, we deal with human suffering. We do not deal with monuments in the words of Shri S. M. Banerjee. I neither deal with steel, nor I deal with cement, nor I deal with fuel. I deal with human beings. I can assure him that if there is any little bit of venom in my heart against a single displaced person whether he comes from Purana Qila or any other place, I shall not be worthy of the office that I am holding. I bear no ill-will, no vengeance. But, I do beg of him, please do not over-state your case. I am glad, my sister from Madhya Pradesh spoke today. We have got 750 M.P.s in this House and the other House. Quite a number of them

have adopted Delhi as their permanent abode. My refugee friends in Delhi have very easy access to them. Just as my sister said, it may not be easy for people from Madhya Pradesh, may be from Assam, may be from the border areas or may be from Tripura, to come to Delhi. But, my friends in Delhi, whether in Purana Qila or any other colony, can have very easy access to Shri S. M. Banerjee and he can go on asking questions.

14 hrs.

It is a great pity that when Shri Banerjee speaks, he does not say a word about the refugees in Kanpur, but he espouses the cause of my friends in Purana Qila. When I contradicted him, he said: 'I do not live in Delhi'. Now, Government took into consideration the interest of those who lived in Delhi, and created these colonies and townships Government allotted them with open eyes and a generous heart. Sir, we have built properties worth about Rs. 20 to 25 crores in Delhi. The number of units is about 50,000. Only a few hundreds of them are not allottable. The rest are all allottable. Today, the value of properties in Delhi has gone up by 300 to 400 per cent. If Government wanted to do any profiteering, I could have implemented the compensation scheme wholly and fully on the assets created by me in Delhi if I had sold them in the public market, but that has never been the policy of the Government. The policy of the Government is to rehabilitate; but I shall certainly see that people outside Delhi get their due share, and that the people in Delhi who are more vocal cannot have it both ways.

May I tell in passing to my friend Shri Naval Prabhakar that if my property in Moti Nagar is not good, my houses in Patel Nagar are leaking, and that my shops in Gaffar Market are tottering, who is requesting him or his constituents to come and purchase them from me? I am not forcing anybody to purchase my property. If they purchase it from me at five

thousand rupees, they are selling it at twenty thousand rupees. I am not asking for any betterment money. But I certainly say that there should be a limit to all kind of concessions. There should be a limit to relaxations. We have gone to the extreme. For the sake of those who have not been able to receive anything from us in the shape of compensation, I propose to finalise the pending cases and take suitable action. In respect of anybody who does not wish to become the owner of a property, I am not forcing on the property to him in Delhi. Let him not become the owner of the property then. If at all he wants to become the owner of the property it will be at his own expense and not at the expense of his neighbour. That must be very clearly understood.

Now, Sir, I will go to the rural aspect of the compensation scheme. I might mention in passing that we have paid up till now Rs 103 crores in four lakhs cases. Out of this, a little over Rs 52 crores have been paid in hard cash. Let me go to the rural aspect of the scheme. In the early stages, in the Punjab, allotments were made to about 4,77,000 persons on a quasi-permanent basis. They were allotted twenty-four lakhs standard acres. I would refer, in this connection, to what Shri Ajit Singh Samhadi referred to. Shri Ajit Singh Sarhadi is a very good advocate. He mentioned about the 2,25,000 cases on whom permanent rights have been conferred, but, Sir, I would say that the land in regard to which permanent rights have been conferred is nineteen lakhs standard acres out of twenty-four lakhs standard acres. The percentage will come to about seventy-eight. Now, the remaining two lakhs persons have to receive only about five lakhs standard acres. The question was asked "Why are they not coming forward to receive the allotment?" I shall give a reply. A substantial number of them are small claimants. They are no longer interested in it. Quite a number of them have been allotted holdings outside Punjab. I believe it is in the knowledge of the hon. Member who raised this point that there are dis-

placed persons who have been allotted lands in Rajasthan, in U.P. and other places. They are not receiving the small allotment in the Punjab, because they know that if they receive the allotment, the other one will be cancelled. Some of them filed claims for rural houses. They are waiting to receive their proportionate compensation in regard to rural houses and if they receive their allotment of land today their claims for rural houses will be wiped out. We have got a large number of Bahawalpuris, Sindhis, Baluchistanis, and people from N.W.F.P. in whose cases *Jamabandi* records have not been received from Pakistan. So, their allotments were not made permanent. We are looking into their claims; we are looking into the oral evidence and when these claims have been looked into and orders issued they will start receiving their allotments.

One other matter referred to by the hon. Member was in regard to rural houses. It is quite true that the number of houses that have to be allotted is very large while the number of rural houses that have been allotted till now is comparatively small. I am looking into the matter and I shall have proper enquiries made. My feeling is as allotment of a rural house is linked with land, if these two lakhs of claimants do not come forward to receive their allotment, no rural house can be allotted to them. That is one possible explanation.

Shri Ajit Singh Sarhadi (Ludhiana)
Though the Ministry gave permanent rights of lands to 2,25,000 cases, rural houses have been allotted to only about 84,000.

Shri Mehr Chand Khanna: I have told him that I am trying to have this matter looked into.

The other possible explanation is this. A good number of the houses have been washed away in the Punjab on account of rains and floods. Now, as I said, I shall look into the whole matter, but what I am trying to tell you, Sir, is this. By and large,

[Shri Mehr Chand Khanna]

the work of compensation which we took up in the year 1955 is nearing completion.

Now, Sir, in regard to my negotiations with Pakistan, I may say, I am rather in a difficult situation because I do not know what to say and what not to say. I have been to Karachi three or four times. I have had meetings with my friends there—some of them are dead and some of them are no longer in office in Pakistan. But, Sir, I will take the House into confidence and tell them of my last interview with Haji Maula Baksh who, about a year ago, was my opposite number in Pakistan. He came to India. I told him that your country and my country have our disputes about canal waters; we have disputes about Kashmir and we may have disputes about some other matters, but here is a dispute in which the two Governments are not concerned. Sir, if I have left some money in the Imperial Bank in Lahore or if Mr Din Mohammad who has gone away to Pakistan has left his own safe deposit in the Patiala Bank, it is a question of helping these unfortunate men because the contractors' claim and the court of ward deposits may be the only assets left with them after partition. The words that Haji Maula Baksh used were: 'I know it is an *amaanat* and I shall see that we do not do, or any country does, any *khayanat* in the *amaanat*.' Unfortunately, Sir, nothing happened after that. I do not want to apportion any blame so far as the Government of Pakistan or anyone outsider was concerned. My object is to appeal to the Government of Pakistan, in the name of humanity, in the name of those persons, whether they had to come from Pakistan into India or they had to go from India to Pakistan, that if we can help them in retrieving their assets which were lying in lockers or safe deposits, there should be no hesitation on the part of the Government of Pakistan.

I wanted to say something about the Chaudhury report, because, Acharya Kripalani, in the course of the general

discussion, made a very scathing remark. He said:

"Here is something again more startling than before. And this is Shri C. P. Chaudhury's report; and Shri C. P. Chaudhury's report investigated into the allotment of evacuee lands in the Punjab and his conclusion is very very illuminating. He says that:

"In the traditional Moghul style, many officials conferred *jajirs* on their friends and relations in utter disregard of legal or moral considerations."

The press has also taken great notice of this report. I have not read the report so far, I must confess. A copy came to our Ministry about a month or two ago. The report covers about one thousand pages. It is being examined by my senior officers in the Ministry, because we are treating it as a secret report. But I am told on authority that nowhere in that report can the passage quoted by Acharya Kripalani be found. As to how he got the information, wherefrom he got the information, I have no idea. But with your permission, I shall give you the brief background of this case.

Between the years 1954—56, various complaints were received from various quarters against the alleged irregularities in the allotment of urban and rural land including gardens in the Punjab. Since the allegations covered a very wide field and related to allotment which had been made from 1949 onwards, it was decided in 1956 by the Ministry of Rehabilitation that an inquiry officer should be appointed for the purpose of shifting the complaints and for making recommendations to Government. The inquiry began in April, 1958, and was completed in the month of February, 1959. The inquiry officer was a senior I.C.S. officer, and his report covers nearly a thousand pages. The report is in two parts. The first gives a general picture of the land resettlement scheme, and

of the background against which the various allocations were made. The second part relates to the details of 70 cases in which, according to the views of the inquiry officer, the circumstances indicate that land allotments were irregular. The report is an interim report, because the findings of the inquiry officer are based only on the material available in the files and do not take into account any other material which might be available, and which would present the other side of the picture.

The report is at present under examination and this examination will necessarily take some time because not only has the report to be scrutinised but also all the files on which the report on each case has been based. This is necessary in order to find out if there is *prima facie* evidence of serious irregularities. It is hoped that this examination of the report and substantiating material will be concluded by the end of April. Thereafter, Government will decide as to what further action, if any, should be taken.

Now, I have told you two important subjects or items with which my Ministry was charged in the year 1954, that is, about four years ago. I have also given you an idea of how far we have been able to achieve our objective. This Ministry was created on account of the circumstances which prevailed immediately after partition. This is not a Ministry which can be made a permanent Ministry. If it was, the real object of rehabilitation would be defeated. Whether I call it suicide in the words of Shri Sadhan Gupta, or whether it may be a funeral oration in the words of Shri Ajit Singh Sarhadi, I feel that the greatest achievement that this Ministry can achieve is to liquidate itself

Pandit Thakur Das Bhargava: That is the right approach.

Shri S. M. Banerjee: He can become the Minister of liquidation.

Shri Mehr Chand Khanna: . . . for the obvious reason that, firstly, I want to complete my work, secondly, I want my displaced friends to be bodily integrated in the life of this country, and I want the displaced person to take his rightful place in this country and not be called a displaced person for all time to come. I do not propose to leave this work undone. I might also say that, because I feel that having given about eleven years of my life, perhaps towards the far end, to this Ministry . . .

Pandit K. C. Sharma (Hapur): He will live long.

Shri Mehr Chand Khanna: . . . I do not want to run away from this work. That is no intention of mine. So, what I propose to do is this. In respect of all those problems which have been mentioned by the hon. Members of this House, I propose to have each matter fully examined; and it is not merely that, about a month ago, I wrote a letter to all my colleagues in the western region, I mean, the Rehabilitation Ministers, and I have asked them, please let me know the residuary problem still remaining in your State which you would like to be resolved. I am receiving notes from them. So I propose to call a conference next month, a conference which may not be only for one day but will be for two, three, four, five or six days. The idea is to sit round the table along with my colleagues, the Rehabilitation Ministers; whether he be from Madhya Pradesh and talks of Mana and Tilda, or whether he be from U.P. and talks of our friends in the Naini Tal and Terai area, I wish to go into this question and see that whatever the residuary problem is, it is examined and we tackle it, and come to grips so that the target that I have laid before myself, that is, completion of this work in the western wing by the 31st of December, 1959, and at the latest by the 31st March, 1960, is achieved.

Now, I should like to turn to the eastern region. **Shri Sadhan Gupta**

[Shri Mehr Chand Khanna]

in his opening remarks, the day before yesterday, made three observations. One was that according to the recommendations of the Ministers' conference in 1954, the camps had not been liquidated. The second was that Bengal had not reached a saturation point. The third was that my policy in the matter of the establishment of small, cottage and medium industries in the eastern region in the private sector was one under which no industries in the private sector could be established in West Bengal. I am sorry Shri Sadhan Gupta is not present in the House.

Let me go back to the year 1954, when the Ministers' conference or committee met and examined the then problem existing in West Bengal. At that time, that is, on the 1st January, 1954, the number of displaced persons in camps was only 64,000. But, as I said a little while ago, the exodus had been going on at an alarming pace in the eastern region. In the year 1954 alone, 47,000 persons went into camps. In 1955 another 86,000 persons went into camps. In 1956 the figure rose to 98,000. My problem on the 1st January, 1957 was 231,000 persons in camps, plus the 64,000 who were already there on the 1st January, 1954. The figure nearly went up to three lakhs. This is a point which needs looking into, which needs to be remembered, that when the Ministers met in 1954 the problem was confined to only 64,000 persons in camps, but by the end of 1956, on account of the economic conditions or the political climate in Pakistan, nearly three lakh persons were taken into camps.

Not only that. In those three years the total number that came by the issue of migration certificates was about seven lakhs, and in addition we had people who came with forged migration certificates, and also through land routes, of an open border, without any border slip or any border certificate.

During the last two years or so, the conditions in the eastern region have

stabilised greatly,—and that I have fully implemented the recommendations of the Ministers Committee. Not that I have only rehabilitated 60,000 persons from camps, but during the last two years I have taken out as many as 1,20,000 persons from camps, but it must be remembered that in spite of this, the number still remains at 1,80,000. That is on account of the fact that nearly three lakh persons came from East Bengal in a very shattered and tattered condition, and we provided them with shelter.

Another point that has been referred to very often in this House and outside is whether Bengal has reached the saturation point or not. As far as the Government of India are concerned, whether we sanction a scheme in West Bengal or a scheme in Madhya Pradesh, the entire expenditure and the funds have to be found by the Government of India. So, it is not material from our point of view whether we rehabilitate persons in West Bengal or in Bihar, because the money has to be spent by us. Hundred per cent advance is made by the Government of India, hundred per cent relief expenditure is borne by the Government of India, and hundred per cent losses are also borne by the Government of India.

We have problems in Madhya Pradesh, we have problems in Bihar. My hon. friend Shri Bibhuti Mishra has talked to me not once, but a number of times, and he usually enquires of me: "Have we not got pressing problems in our own State? Don't you think that you should rehabilitate your Bengalee friends in Bengal and not bring them to Bihar, because by bringing extra population into Bihar or into Orissa, you are creating a problem for us, though you may be resolving a part of the problem for yourself?" There is something in it, but I must be very grateful to the Chief Ministers of Orissa, Bihar, U.P., and Madhya Pradesh that, in spite of their own local difficulties, they have come forward very willingly and very cheerfully offering valuable lands for

the rehabilitation of my unfortunate friends from East Pakistan.

A little while ago, Shri Ghosal stated that in spite of the recommendations of the Ministers conference, these displaced persons were being taken to States outside West Bengal. I do not plead guilty in this direction at all. It was in the year 1950, as far back as nine years ago, that this policy of the dispersal of displaced persons from West Bengal was laid down, and all the parties in West Bengal, whether they belong to my side or the other side of the House, have been in agreement with it. Our first movements started to Andamans. That was in 1950. After that, up till now about 30,000 families have been taken out of West Bengal to States like Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and UP. It is the continuation of the old policy that we are following.

There has been a certain amount of opposition to the Dandakaranya scheme, I am glad to say not on this side of the House. In fact, even the PSP Members spoke in favour of this, but I wish to tell the House that for the last two years or so I have been taking displaced persons to Ambikapur and Dharamjaigarh in Madhya Pradesh, and if I took now another batch to Bastar or Koraput, what is the difference. What is the difference, I want to know, between Dharamjaigarh and Ambikapur in Madhya Pradesh and Bastar, or for the matter of that, Jagadlpur or Koraput in Orissa, or maybe some other place in Madhya Pradesh? After all, there are people in Orissa. I have reclaimed the foreshore of the Chilka Lake, my hon friend Shri Panigrahi knows it. It is the same two States where the people are being taken to. But now I will take you into confidence and tell you why there is opposition today. The opposition is based on the ground and the consideration that like the western region, we are now in sight of the solution of the rehabilitation problem in the eastern region as well.

There used to be desertions before, I admit and I concede, but may I hum-

bly ask whether there have been any desertions from Bihar, from U.P., from Madhya Pradesh, from Orissa and from Rajasthan during the last two or three years? Not a single displaced person who was taken there has deserted, and we have used no pressure, no compulsion. Not a single person has been taken to these States against his or her will. It has been entirely a free movement.

The reason has been that we have taken two specific matters into consideration. One is that we have given each person an economic holding, much more, I believe, than the local person has. It is now costing me about Rs 5,000 for rehabilitation of each family. The other is that we try and take these people into sizeable blocks. I try and keep their community and cultural life intact. In spite of the inroads from Bengal, and in spite of the long harangues by some of my friends whom I do not wish to name, we have succeeded, and succeeded well, in our rehabilitation schemes in these States.

The problem that we assessed a year ago, or about ten months ago, was that there were about 45,000 families in camps in West Bengal alone had at that time also about 15 to 20 thousand persons in Tripura, the same number in Bihar and about 5,000 in the Charbettiah camp. In locating lands in these States we have been successful, but we have been able to find land only in small bits and small areas. Now, if you take, say, 40,000 families and you allot each family even six to seven acres, you need anything like 2 to 2½ lakh acres of land. That land is not available in any State. So we looked into an area where we could find there was a vacuum to the extent that extra population could be taken, pressure on land was not great and people could be rehabilitated in big blocks without causing any local disturbance. And we also saw one thing more, that the conditions in that area were more or less akin to the conditions prevailing in Bengal. We came across this area

[Shri Mehr Chand Khanna] which is called Dandakaranya. I wish to pay a tribute or rather wish to convey my grateful thanks to the Governments of Bihar and Madhya Pradesh

Shri Fanigrāhi (Pur) And Orissa

Shri Mehr Chand Khanna: ..and Orissa for having agreed to place thousand of acres of land at the disposal of the Government of India for development and for being allotted to displaced persons for their rehabilitation. I have taken a couple of batches there My movement may have been a little slow, but I do not want to go very fast The Dandakaranya scheme is quite different from an average scheme that we have been following up till now in any other State In other States before, we used to rehabilitate people and till then keep them on doles That is no longer our policy in Dandakaranya In Dandakaranya, every persons who is taken—and I have accepted that responsibility—shall be provided with work till he or his family has been rehabilitated. So I have to provide work to each family that is taken to Dandakaranya To provide work to 40,000 or 30,000 families is a colossal task

Three or four months ago, some of my friends in West Bengal launched a resistance movement As usual, they took out processions, they held meetings We watched the situation for some time But the House will be glad to know that for the first time in Calcutta the UCRC or its patrons had to eat the humble pie because that resistance movement had neither the sympathies of the displaced persons, because by now they had found out who were their friends and who wanted to use them for their political purpose, nor the support of the general population in West Bengal

Shri Aurobindo Ghosal: How many were arrested?

Shri Mehr Chand Khanna: I will make a brief statement, if I am not asked to substantiate it My information is—it may be entirely incorrect—that on every day that I give doles to my refugee friends round about Calcutta, a particular party gets one anna in the rupee from those displaced persons I am not naming any political party They make about Rs 70,000 or Rs 80,000 a month. With that, they have got a large number of workers (Interruption by Shri S. M Banerjee) Do not get excited You are from Kanpur I am talking of West Bengal On every day, when it is intended to take out a procession, whether they want to honour me by their presence or they want to go to the residence of Dr B C Roy, people are paid from the doles that I give at the rate of Re 1, 12 annas and 8 annas for each volunteer You might ask me why this discrimination? The man who is in the front gets Re 1, the man in the middle gets 12 annas and he at the back 8 annas, for the obvious reason that if they had to face something like what happened outside Jannagar House the other day, the man in the front gets Re 1 and the man at the back gets 8 annas

Shri Nath Pal (Rajapur) His reference to Jannagar House is wrong

Mr. Deputy-Speaker: He has already said that he might be wrong Therefore, there is no need to pursue it

Shri Nath Pal: That may be true of Calcutta But not about what happened here, It may prejudice the case

Shri Mehr Chand Khanna: I will make a categorical statement which I can own and for which I take full responsibility When this movement was about to be launched and we had fully judged the public opinion in West Bengal more so of the Press who supported this Dandakaranya scheme fully and rightly, I passed orders. I am making this statement for the first time I wrote to the Government of West Bengal that when this movement was launched on

every day at 3 O'clock—that is the time for agitation or demonstration—there should be a roll call in each camp, and if a refugee was not present, his dole for the day should be deducted, so that he could not have the best of both the worlds at the same time. The second thing I said was that the name of every refugee who was arrested should be removed from the camp register. There are only about 250 families or 250 persons in all whose names have been removed from the camp register on account of the part that they took in this agitation. A few days ago, Shri Jyoti Basu, Leader of the Opposition in West Bengal came to see me in Delhi—he also saw Dr B C Roy in Calcutta—and requested that the doles of these unfortunate persons should be restored. We are looking into the matter.

As I said just now, I have nothing against the displaced persons. The Government which can spend Rs 350 crores on their rehabilitation from their own revenues, can pay them Rs 185 crores in the shape of compensation and over and above that give them 19 lakh standard acres of land, has no intention of taking away the small pittance from A refugee or B refugee. But we certainly do not want them to be made tools of certain political parties for their own political ends.

Another reference that was made was in relation to my policy. It is a distortion of truth, or I might say it is a complete perversion to level a charge of that nature against me and my Ministry. Apart from what has been done during the last few years, in this year alone that is 1958-59, 26 small cottage industries schemes were sanctioned at a cost of about Rs 31 lakhs. The total number of sanctioned schemes so far is 123, involving an expenditure of Rs 104 lakhs with an employment potential of 14,000 displaced persons. Over and above that, we have sanctioned 18

medium industrial schemes. There, our capital investment is likely to be anything between Rs 2½ crores—Rs 3 crores. All these schemes have been sanctioned in West Bengal. Some of them are in the private sector and some in the public sector. That is not all. Lately, we have set up a Rehabilitation Industries Corporation with the sole object of providing employment to displaced persons from East Pakistan. It has been charged with the task of setting up industries in the eastern region, whether in the public sector or in the private sector and to see that they are set up expeditiously, because our main idea is that as those who will be taken to Dandakaranya will be rehabilitated there, but those who are in West Bengal and have only been partially rehabilitated should be provided with employment. The capital of that Industries Corporation is going to be Rs 10 crores. As regards the directors, I might give two or three names of renowned men from West Bengal—Shri B P Singh Roy, Shri D N Sen, Shri K K Roy. The Chairman is Shri G D Birla. I am grateful to him for having accepted the Chairmanship of this Industries Corporation.

Shri Vasudevan Nair: How many of the schemes have been implemented? It is not a question of sanctioning. How many of them have been implemented?

Shri Mehr Chand Khanna: If the hon. Member wants information regarding the schemes that have been sanctioned before.

Shri Vasudevan Nair: Implemented.

Shri Mehr Chand Khanna: This Corporation was set up only a few days ago.

Shri Vasudevan Nair: You said—other schemes.

Shri Mehr Chand Khanna: As regards other schemes, of the 18 that

[Shri Mehr Chand Khanna]

were sanctioned during the last 2 or 3 years, quite a good few have been implemented and others are in the process of implementation. With a view to set up an industry costing about Rs. 50 lakhs to a crore of rupees, a number of things have to be taken into consideration. We have to import the machinery from abroad; we have to arrange for foreign exchange, we have to take the machinery on to the site and then, water has to be provided; electricity has to be provided. In some of the areas in West Bengal, electricity is not available; it is not a commercial load for any concern now to put up or provide electricity in that area. We have to subsidise all these things. So, what I am trying to tell the House is this, that to accuse the Government of apathy in the matter of rehabilitation of displaced persons from East Pakistan is something which does not become or behove responsible men, more so, who occupy such responsible positions and, when we have spent up till now over Rs 100 crores on the relief and rehabilitation of these displaced persons from East Pakistan. Our Budget for the eastern region, as you know, is Rs 17 crores, and for the Dandakaranya, it is another Rs 6 crores and for the Industries Corporation we have made a provision of Rs 3 crores this year. The Budget for the eastern region alone this year is about Rs 27 crores. This is not a small sum of money.

And, to say that we have not been able to rehabilitate any persons up till now is again not correct. We have given loans to about 5 lakh families in the eastern region. Mr Ghose said the other day that, while in the western region I have built about 2 lakh tenements, our performance in the eastern region was very poor. We have given urban loans to anything between one lakh and a quarter to one lakh and half of families in the eastern region for the construction of

their houses. The amount is Rs. 16 crores.

The only difference between the western and the eastern region is that whereas in the western region, Government took to direct construction and the refugee is a tenant and ultimately, if he wishes to become the owner he has to pay the price of that house—in the eastern region, you wanted 4 or 5 kathas of land, you wanted a little kitchen garden, you wanted to have your own cultural surroundings and natural heritage, and the result was that instead of the Government launching upon a housing programme, we gave loans to this lakh and a quarter or a lakh and a half of families who are the owners of their property. It is a different matter—about the payment of arrear of loans or the interest that is due and it is only 2, 3 or 4 per cent—but we did not undertake direct construction work in that area.

One more point and I will finish. You have already given me a big latitude. That is about this question of the saturation point having been reached or not in the West Bengal. Every time we hear about the Ishaque Report. This Mr Ishaque, I heard in Bengal, lived before partition or died before partition or went to Pakistan, I do not know. He was an officer of the Muslim League Ministry. He gave a certain report and this report has been fully examined by the Government of West Bengal. I will read one passage. I do not want to take much time of the House. What is the significance of the Report? Is it the land that is available in West Bengal. I am quoting from a statement made by Dr B C Roy, the Chief Minister of West Bengal.

"Ishaque's Report (1944-45) is often quoted to show that adequate land is available in West Bengal for rehabilitation of agriculturists. Description such as 'uncultivable waste' and 'cultivable waste' on the basis of this

report is totally misleading, if shorn of the contexts. For example, 'uncultivable waste land' as described by some, which in Ishaque's Report has been described as unculturable waste actually consists of tanks and rivers, jheels and marshy lands, roads and Railways, temples, mosques, shops, homesteads etc. The figure 1:98 million acres for culturable waste within West Bengal sometimes quoted on the basis of Ishaque's Report includes bhita, grazing ground, jungles, play grounds etc. Besides, Ishaque included within it old fallow land, that is to say land laying fallow for more than three years, which belonged to individual cultivators and were brought under cultivation by them from time to time as and when possible. Whatever might have been the position when Ishaque conducted his survey, the position seems to have considerably changed during all these years. There has been a natural increase in population and more land has been brought under plough. To cite one example, in Ishaque's Report culturable waste in Howrah was shown as 12,057.54 acres as against 4,307 acres as found in the latest survey by the D.L.R."

Now, this gives the background of this case. The land, according to our information, that is available or can become available in the whole of West Bengal is not more than 1 lakh of acres. This, again, is contained in a pamphlet or a statement issued by the Government of West Bengal under the heading Notes or comments regarding the rehabilitation of refugees. The total area given is 1,03,000 acres of which about 80,000 acres are in the district of Midnapore and the rest scattered in small bits over the whole of West Bengal.

A friend of mine yesterday hinted—and very rightly—that we were taking great risks in developing lands in Sunderbans, that is, Hirobhanga lands under the river Teesta near

Jalpaiguri and in Midnapore. That is so. These are all waste land, marginal and sub-marginal. If they had any potential they would have been brought under the plough and would have been developed long ago. We are taking this risk—and, perhaps, we are taking this risk deliberately—to show that in spite of the dangers being there, the intention of the Government is that if any land can be developed within West Bengal, we will give the State Government every possible facility.

We have given them Rs 15 lakhs for the purchase of machinery. I have arranged expert advice for them from the Council of Agricultural Research. Our capital investment on these lands is going to be nearly Rs. 1 crore. So, to go on harping on the old story that land is available in West Bengal will do no good to the displaced persons whose cause is, as they allege, near to them.

Here is a scheme, the Dandakaranya scheme which has been thought of and which is being implemented. We have taken care to see and we have got experts from all directions dealing with every aspect of the matter, whether it is malaria, whether it is soil conservation, whether it is contour bunding, whether it is well water etc. All these things are being taken into consideration.

I would appeal to them that the work of this Ministry is going to be completed within the next 2 years. Ten years or eleven years have already elapsed and the time is a very important factor. We have already taken about 1,20,000 persons out of the camps during the last two years. I am aiming at an average—it is about 10,000 persons a month and at this rate, I am hoping that within a year, maybe fifteen months or a maximum of a year and a half, we should be able to take out all our camp population from the camps in West Bengal. We are taking some of them to Dandakaranya and others we are trying to rehabilitate within the State itself.

[Shri Mehr Chand Khanna]

My hon friends also made references to Assam and Tripura. My main problem today is confined to West Bengal. I have been lately to Assam and Tripura myself and I have held discussions with the Chief Minister of Assam and the Chief Commissioner of Tripura. We have examined the entire problem, we have looked into the residuary aspects of the problem. We are hoping that within about a year, we should be able to resolve the residuary problem in Assam and Tripura. As far as Assam is concerned over 80 per cent of the refugee population had been there since 1952. There are no camps in Assam. It is only about 20 per cent of the refugees that have come to Assam during the last seven years. In Tripura up till now we have spent Rs 10 crores on rehabilitation. When I went to Tripura about two months ago, my friend who spoke last was there and as generally happens, he arranged big processions and demonstrations for me and even arranged a hunger strike outside the house of the Chief Commissioner.

Shri Dasaratha Deb. People die

Shri Mehr Chand Khanna. My Demands for Grants were to start on the 7th and I got a telegram on that very day and a news item appeared in the *Amrit Bazar Patrika* that 19 persons had gone on hunger strike. The number of displaced persons in Tripura is nearly 3½ lakhs—about 50,000 or 60,000 families. We have already spent about Rs 10 crores on their rehabilitation. My intention is that the residuary work should be completed in the shortest possible period and the remaining work, if any, has to be integrated with the normal work of the State. This Ministry, as I said in the beginning—I am closing—was created to meet an emergency created on account of the Partition of the country. In its very nature and context it has to complete its work one day. But this Ministry was dealing with a large number of

subjects like housing, training, education, medicine, industry, home for infirm, etc. There are permanent Ministries of the Government of India set up to handle all these subjects. There may have been some need for my Ministry in the initial stages but today when the work of industrialisation has gone ahead and schemes have been sanctioned, I see no reason why this work cannot be handled by the Ministry of Commerce and Industry. I give stipends, they are paid according to certain rate which has been laid down. This work can be easily passed on to the Ministry of Education. We have done so as far as the Western region is concerned. I propose that during the next two years the work which is of a more permanent nature should be transferred to the sister Ministries of the Government of India who have been dealing with them always. As far as the residuary work is concerned, I am looking into the entire matter and I can assure you that we will try to complete that work successfully as we have done in the western region and it will be a great credit to a man who comes from the west—I want this to be remembered that at no time have we made any discrimination in the case of displaced persons from East Pakistan and nobody would be happier than me a man coming from the west, if during the next two years as I am hoping, the problem of the displaced persons from East Pakistan is also resolved.

Shri Dasaratha Deb. The Minister did not reply to the point regarding the refugees of Tripura who came after 1954 and who are demanding now an increase in agricultural loan and a second set of loans. These people are now on hunger strike. He did not reply as to what he is going to do regarding this.

Shri Mehr Chand Khanna. The day before yesterday when I read this news item I sent, on my own, to the Chief Commissioner of Tripura a telegram

If it is a hard case, real and deserving case, the loan should be paid, but if the loan is sought through pressure tactics, not a single person is to be advanced a single penny.

Mr. Deputy-Speaker: Shall I put any cut motion separately?

Shri T. B. Vittal Rao: All cut motions may be put together.

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put all the cut motions to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos 72, 73 and 128 relating to the Ministry of Rehabilitation."

The motion was adopted

[*The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha are reproduced below—Ed*]

DEMAND No 72—MINISTRY OF REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 34,21,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Ministry of Rehabilitation'"

DEMAND No 73—EXPENDITURE ON DISPLACED PERSONS AND MINORITIES

"That a sum not exceeding Rs 18,95,00,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

the 31st day of March, 1960, in respect of 'Expenditure on Displaced Persons and Minorities'.

DEMAND No. 128—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 18,51,87,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Rehabilitation'."

Ministry of Community Development and Co-operation

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up discussion on Demands Nos. 6, 7 and 108 relating to the Ministry of Community Development and Co-operation for which eight hours have been allotted. Hon. Members desirous of moving cut motions may hand over at the table within fifteen minutes the numbers of the selected cut motions. I shall treat them as moved if the Members in whose names these cut motions stand are present in the House and the motions are in order

DEMAND No. 6—MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

"That a sum not exceeding Rs 25,12,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of 'Ministry of Community Development and Co-operation'"

DEMAND No 7—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SERVICE AND CO-OPERATION

"That a sum not exceeding Rs 18 88,90,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1960 in respect of 'Community Development Projects, National Extension Service and Co-operation'"